https://www.facebook.com/Kamal.Sandesh/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

भारत और जापान के बीच 15 समझौतों पर हस्ताक्षर

वर्ष-12, अंक-19, 01-15 अक्टूबर, 2017 (पाक्षिक) ₹20

'संकल्प से सिद्धि तक'

'सेवा दिवस के तौर पर मनाना है नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन'

स्वच्छता में निवेश का अर्थशास्त्र

'झारखंड के विकास के लिए अहर्निश कार्य कर रही है भाजपा सरकार'

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के झारखंड एवं उत्तराखंड प्रवास की झलकियां

रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय की ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन करते हुए

रांची में भाजपा पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए

देहरादून में पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए

देहरादून में जनाभिवादन स्वीकार करते हुए

कांगड़ा में 'युवा हुंकार रैली' के दौरान हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं द्वारा भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह का स्वागत

कांगड़ा में 'युवा हुंकार रैली' में उपस्थित विशाल जन-समुदाय का दृश्य

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in
mail@kamalsandesh.com
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

11 **'संकल्प से सिद्धि' जनांदोलन का आह्वान**

गत 25 सितंबर, 2017 को नई दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव श्री भूपेंद्र यादव ने इस प्रस्ताव को...

वैचारिकी

भारतीय जनसंघ की अर्थ नीति 21

श्रद्धांजलि

मार्शल अर्जन सिंह और महंत चांद नाथ 23

लेख

स्वच्छता में निवेश का अर्थशास्त्र / अरुण जेटली 26

अन्य

यूपीए सरकार की तुलना में मोदी सरकार ने झारखंड को तीन गुना ज्यादा सहायता दी है: अमित शाह 16

'सेवा दिवस के तौर पर मनाना है नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन' 24

'राज्य में विकास की बयार के लिए परिवर्तन लाना है' 28

आपको रोजगार के लिए पहाड़ छोड़ना पड़े, ऐसी स्थिति नहीं आने दी जाएगी : अमित शाह 29

'ममता सरकार की तुष्टीकरण नीति से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है' 30

'सौभाग्य' योजना का शुभारंभ 31

'गुजरात की समृद्धि में सहकारी संस्थाओं का योगदान अमूल्य है' 32

स्थायी स्तंभ

सोशल मीडिया से 04

पत्र-पत्रिकाओं से 33

स्फुट विचार 33

संगठनात्मक गतिविधियां

06 **हर मोर्चे पर सफल साबित हुई है मोदी सरकार: अमित शाह**

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 25 सितंबर, 2017 को दिल्ली...

10 **लोकतंत्र में जन-भागीदारी देश के विकास का आधारभूत अवयव है: नरेन्द्र मोदी**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 सितंबर...

सरकार की उपलब्धियां

19 **भारत और जापान के बीच 15 समझौतों पर हस्ताक्षर**

जापानी प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे की दो दिवसीय भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच...

20 **मनरेगा कामगारों का 96 प्रतिशत भुगतान सीधे बैंक खातों में जमा**

पिछले दो वर्षों में मनरेगा योजना के कार्यान्वयन में प्रमुख बदलाव देखे गए हैं। आईसीटी उपकरणों के...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

आइए, हम स्वच्छ भारत के लिए सक्रिय रूप से आंदोलन में भाग लें और महात्मा गांधी के सपने को पूरा करें।

@AmitShah

यदि कुछ लोग सोचते हैं कि वह हिंसा से भाजपा को रोक सकते हैं तो वह गलत है। हिंसा का कीचड़ भाजपा पर जितना उछाला जाएगा, कमल उतना और खिलेगा।

@rsprasad

भारत 95 मोबाइल विनिर्माण कारखानों की स्थापना के साथ एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण केंद्र बन रहा है।

@KailashOnline

तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी। पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर रही आपकी तुष्टिकरण की नीति से हम बंगाल को हर हाल में बचाएंगे।

facebook

ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए राजस्थान सरकार 'स्वच्छ भारत मिशन' (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता को बढ़ावा देने में जुटी है। भारत सरकार के सहयोग से राजस्थान की 6499 ग्राम पंचायतें अब ODF जोन हैं। स्वच्छ है राजस्थान, स्वस्थ है राजस्थान। — **वसुंधरा राजे**

केंद्र की आत्मा योजना के मॉडल पर बनी नई किसान सम्मान योजना के तहत हर साल राज्य के लगभग 3000 किसानों को 10 हजार से 50 हजार रुपए तक का पुरस्कार दिया जाएगा। शुरुआत रबी फसल के मौसम से होगी। किसानों की आय के साथ उनका मान बढ़ाने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। — **सुशील कुमार मोदी**

गरीबों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य के 26 सरकारी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। साथ ही सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ़ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड एडवांस टेक्नोलोजी (CIPEAT) में जनवरी 2018 से स्किल डेवलपमेंट के कोर्स शुरू किए जाएंगे। — **त्रिवेन्द्र सिंह रावत**

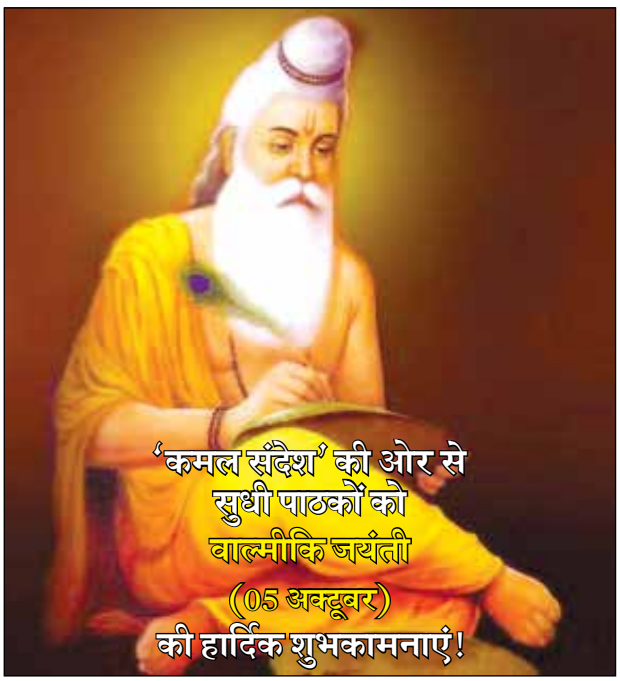

कार्यकर्ताओं के कंधे पर है महती जिम्मेदारी

पं. दीनदयाल उपाध्याय जन्मशताब्दी वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक से कार्यकर्ताओं में मां भारती के सेवा में समर्पित रहने के लिये एक नई ऊर्जा एवं उमंग का संचार हुआ है। जैसाकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जैसे–जैसे भाजपा का जनसमर्थन व्यापक होता जा रहा है भाजपा एवं इसके कार्यकर्ताओं की ओर लोग आशा के साथ देख रहे हैं, जिससे अब उनके कंधों पर वृहत दायित्व आ गया है। अब जबकि देश 'नये भारत' के लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर बढ़ चला है, संगठन समाज के हर वर्ग में पहुंचकर सरकार की अभिनव योजनाओं से जन–जन को जोड़ रहा है। देश में व्यापक परिवर्तन की बयार बह रही है, उसके केन्द्र में समाज के गरीब, वंचित, शोषित वर्ग है और जिसका लक्ष्य गांव, गरीब एवं किसान का उत्थान है। परिणामकारी सुधारों को कार्यान्वित करने तथा भ्रष्टाचार, कालाधन एवं आतंकवाद की कमर तोड़ने की राजनैतिक इच्छाशक्ति को जन–जन का अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। देश 'नए भारत' के लक्ष्यों को प्राप्त करने को कृत–संकल्पित हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व में जब भाजपा–नीत केन्द्र सरकार अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित दिख रही है, देश हर मोर्चे पर जबरदस्त उपलब्धियां प्राप्त कर रहा है। यह पहली बार है जब आतंकवाद के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेन्स' की नीति इतनी कड़ाई से क्रियान्वित की जा रही है तथा अलगाववादियों को अलग–थलग कर उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। भारत की आवाज को दुनिया के विभिन्न मंचों पर गंभीरता से सुना जा रहा है तथा विश्व के अनेक देश भारत का समर्थन कर रहे हैं। गरीबों के कल्याण के लिये क्रियान्वित बड़ी संख्या में योजनाएं ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल रही हैं या गरीबों के चेहरों पर मुस्कान लाने में सफल हो रही हैं। युवा, महिला, दलित एवं जनजातियों के लिये संभावनाओं के नए द्वार खोले जा रहे हैं, जिससे उन्हें नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। नई कार्य–संस्कृति एवं तकनीकी से प्रेरित शासन व्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों में नए–नए आयाम स्थापित कर रहा है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने ठीक कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने वंशवादी, जातिवादी एवं तुष्टिकरण की राजनीति का पटाक्षेप कर 'परफॉरमेंस' की राजनीति का नया युग प्रारंभ किया है। केंद्र की भाजपा–नीत सरकार ने यह दिखा दिया है कि पारदर्शिता, निर्णायक, संवेदनशील लोकाभिमुख सरकार किस प्रकार से पूरी व्यवस्था को परिवर्तित कर उल्लेखनीय परिणाम दे सकती है। आज कोई भी इससे इंकार नहीं कर सकता की मात्र साढ़े तीन वर्षों में पूरी तस्वीर बदल चुकी है तथा भारत कांग्रेस–नीत संप्रग की लूट, भ्रष्टाचार, घोटाले, 'पॉलिसी पैरालिसिस' तथा कुशासन से बाहर निकल चुका है, जबकि विपक्ष खोखले आरोपों से अपनी राजनैतिक रोटियां सेंकना चाहता है। कांग्रेस एवं इसके सहयोगियों के नकारात्मक रुख के कारण आज उनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है तथा वे देश की राजनीति के हाशिये पर पड़े हुए हैं।

देश में व्यापक परिवर्तन की बयार बह रही है, उसके केन्द्र में समाज के गरीब, वंचित, शोषित वर्ग है और जिसका लक्ष्य गांव, गरीब एवं किसान का उत्थान है। परिणामकारी सुधारों को कार्यान्वित करने तथा भ्रष्टाचार, कालाधन एवं आतंकवाद की कमर तोड़ने की राजनैतिक इच्छाशक्ति को जन–जन का अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। देश 'नए भारत' के लक्ष्यों को प्राप्त करने को कृत–संकल्पित हैं।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक ने जहां सरकार की विभिन्न पहलों का स्वागत किया, वहीं 'संकल्प से सिद्धि' आंदोलन का भरपूर समर्थन किया। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गरीबी, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद तथा संप्रदायवाद मुक्त तथा स्वच्छ भारत के लिये सभी को एकजुट होने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी कार्यकर्ताओं को सरकार के कार्यक्रमों तथा जनता के बीच सेतु बनने का आह्वान किया है, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ जन–जन तक पहुंचे। संगठन अमित शाह के नेतृत्व में नई उत्साह एवं उमंग से भरा हुआ है तथा उनके अनेक प्रदेशों में प्रवास से संगठन में ऊर्जा एवं संकल्पशक्ति पैदा हुई है। जैसे–जैसे भाजपा का विस्तार पूरे देश में हो रहा है, लोग नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के उज्ज्वल भविष्य के लिये बड़ी संख्या में पार्टी से जुड़ रहे हैं। यह समय है कि पुनः मां भारती के सेवा में समर्पित होने का संकल्प दुहराया जाय। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

हर मोर्चे पर सफल साबित हुई है मोदी सरकार: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 25 सितंबर, 2017 को नई दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में संपन्न हुई, जिसमें भाजपा राष्ट्रीय पदाधिकारियों, प्रदेश पदाधिकारियों, भाजपा सांसदों एवं विधायकों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने की। इस बैठक में जहां संगठन की प्रगति की समीक्षा की गई, वहीं आगामी योजनाएं भी बनाई गईं। बैठक में अध्यक्षीय भाषण देते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा परफॉर्मेंस की राजनीति में विश्वास करती है। हम गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि 2019 में वर्तमान नेतृत्व के द्वारा एक नया भारत बनाया जाएगा"।
हम अपने सुधी पाठकों के लिए अध्यक्षीय भाषण के प्रमुख अंश प्रकाशित कर रहे हैं:

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 25 सितंबर को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक (विस्तृत) एवं जन-प्रतिनिधि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया और विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, वरिष्ठ भाजपा नेता सर्वश्री लालकृष्ण आडवाणी एवं डॉ. मुरली मनोहर जोशी, गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह एवं वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पिछले वर्ष कोझिकोड की राष्ट्रीय परिषद् की बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मशती वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि आज मुझे कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि पिछले एक साल में देश का हर गरीब पार्टी और सरकार से जुड़ा है।

श्री शाह ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सिद्धांत एवं राष्ट्रवाद के आधार पर चलने की प्रेरणा दी थी। उन्होंने कहा कि सच्चे अर्थों में पंडित दीनदयाल जी शुचिता, सिद्धांत एवं राष्ट्रवाद के आदर्श थे। उन्होंने कहा कि हमारे संगठन की आत्मा हमारे कार्यकर्ता हैं, कार्यक्रमों की प्रेरणा हमारे सिद्धांत हैं और हमारा लक्ष्य भारत को विश्वगुरु के पद पर पुनर्प्रतिष्ठित करना है। उन्होंने कहा कि कालीकट राष्ट्रीय परिषद् बैठक में हमने पंडित दीनदयाल जन्मशती वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाने के साथ-साथ पार्टी के विस्तार एवं संगठन की मजबूती के लिए भी काम करने की योजना बनाई थी और प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर देश भर में लगभग चार लाख कार्यकर्ता 15 दिन, 6 महीने और एक साल के लिए बूथ स्तर पर पार्टी की मजबूती के लिए काम करने निकले। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मशती विस्तारकों ने मोदी सरकार की उपलब्धियों, पार्टी की विचारधारा एवं को बूथ स्तर तक पहुंचाने के लिए अथक परिश्रम किया। उन्होंने कहा कि कुल 3,92,802 पूर्णकालिक कार्यकर्ता लगभग 9,69,000 बूथों पर जनसंपर्क करने का लक्ष्य लेकर निकले जिसमें से 6,13,947 बूथ पर जनसंपर्क का कार्य पूरा कर लिया गया है, लगभग डेढ़ लाख बूथों पर और कार्यक्रम होने वाले हैं, कुछ ही दिनों में कुल मिलाकर 7,63,947 बूथों पर जनसंपर्क करने का काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त 1198 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये गए जिसमें चार लाख कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया और इसमें से 4,682 विस्तारक 6 महीने और एक साल के लिए पूर्णकालिक के रूप में पार्टी की विचारधारा का विस्तार करने क्षेत्रों में जायेंगे।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मैंने बूथ प्रवास और विस्तृत प्रवास योजना के तहत 25 राज्यों का प्रवास किया है और हर जगह कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बनता है। पुदुच्चेरी की कार्यकर्ता लक्ष्मी का उदाहरण देते हुए कहा कि जब लक्ष्मी अपने पति और बेटे से दूर हॉस्टल में रह कर

पार्टी का प्रचार करने अपनी लूना पर निकलती है तब पता चलता है कि पार्टी के कार्यकर्ता कितने परिश्रम से पार्टी के विकास के लिए लगे हुए हैं।

श्री शाह ने कहा कि लगभग कार्यालय निर्माण का भी कार्य प्रगति पर है, इसका लगभग 85% कार्य पूरा कर लिया गया है, 25 राज्यों में लाइब्रेरी एवं ई-लाइब्रेरी के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है, सारे राज्यों में विभागों एवं प्रकल्पों के निर्माण का काम भी समाप्त कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि 10 सदस्यों से शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी आज 11 करोड़ से अधिक सदस्यों के साथ विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, आज हमारे 1387 विधायक हैं, 325 से अधिक सांसद हैं, 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कुछ राज्यों में सहयोगियों के साथ हम सरकार में हैं और केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। उन्होंने कहा कि मैंने 9 अगस्त 2014 को कहा था, एक बार फिर इसे दुहरा रहा हूं कि यह हमारा सर्वोच्च लक्ष्य नहीं है, हमें केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ओडिशा, त्रिपुरा, तेलंगाना सहित उत्तर पूर्व के सुदूर राज्यों के हर बूथ तक संगठन और पार्टी की विचारधारा को पहुंचाना है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि एनडीए के घटक दलों द्वारा प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी चुने जाने के बाद अपने पहले ही संबोधन में श्री नरेन्द्र मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि केंद्र में बननेवाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, आदिवासी, शोषित, पीड़ित, युवा एवं महिलाओं की सरकार होगी और पिछले तीन सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार ने इसे अक्षरशः सिद्ध कर के दिखाया है।

श्री शाह ने कहा कि आजादी के 70 साल बाद भी देश के लगभग 60 करोड़ लोगों के पास अपना बैंक अकाउंट तक नहीं था। उन्होंने कहा कि पिछले तीन साल में ही मोदी सरकार ने 29 करोड़ से अधिक जन-धन खाते खोल कर गरीब को देश के अर्थतंत्र की मुख्यधारा से जोड़ने का सफल प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान लगभग 2.80 करोड़ गरीब महिलाओं को गैस सिलिंडर देकर उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया गया है, 15 करोड़ से अधिक लोगों को विभिन्न बीमा योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है, 7.64 करोड़ से अधिक लोगों को मुद्रा बैंक के माध्यम से स्वरोजगार के लिए बिना गारंटी के आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराये गए हैं। उन्होंने कहा कि आजादी से लेकर 2014 तक देश में ऑप्टिक फाइबर की लंबाई केवल 600 किलोमीटर थी जबकि 2014 से अब तक केवल तीन साल में मोदी सरकार ने ऑप्टिक फाइबर को 600 किलोमीटर से बढ़ा कर दो लाख किलोमीटर किया है। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 साल बाद भी देश के 19 हजार गांव अंधेरे में जीने को विवश थे, इसमें से 14 हजार गांवों में बिजली पहुंचाने का काम पूरा कर लिया गया है, मई 2018 तक देश के हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के तीन साल में साढ़े चार करोड़ शौचालय का निर्माण किया गया ताकि महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देश के किसानों की आय को दुगुना करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को मिलने वाली आपदा सहायता में वृद्धि की गई है, नीम कोटेड यूरिया की शुरुआत की गई है, खाद की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता कराई गई है, स्वायल हेल्थ कार्ड से मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रयास किये गए हैं, साथ ही प्रधानमत्री सिंचाई योजना, ई-मंडी, फसल बीमा योजना और श्वेत क्रांति एवं ब्लू क्रांति के जरिये किसानों के लिए योजनाओं का एक सम्पुट तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि आज देश की जनता को इस बात का विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार देश के विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफी विकास किया है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने नर्मदा बांध को राष्ट्र को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जापान के सहयोग से बुलेट ट्रेन की नींव रख कर विकास की राह में एक कदम और आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना के माध्यम से देश के गरीबों को भी हवाई यात्रा का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि जेनरिक दवाई और स्टैंट एवं घुटना प्रत्यर्पण के मूल्य में कमी से देश के गरीब वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचा है।

आजादी के 70 साल बाद भी देश के लगभग 60 करोड़ लोगों के पास अपना बैंक अकाउंट तक नहीं था। उन्होंने कहा कि पिछले तीन साल में ही मोदी सरकार ने 29 करोड़ से अधिक जन-धन खाते खोल कर गरीब को देश के अर्थतंत्र की मुख्यधारा से जोड़ने का सफल प्रयास किया है।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर करारा प्रहार करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर वहां से प्रश्न पूछते हैं कि मोदी सरकार की उपलब्धि क्या है? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी, आप उपलब्धियां गिनते – गिनते थक जाओगे, लेकिन तीन साल में हमने सबसे बड़ा काम यह किया है कि हमने आपके 12 लाख करोड़ रुपये का घपला-घोटाला करने वाली यूपीए सरकार की जगह एक भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी सरकार दी है जिसपर हमारे विरोधी

भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सके हैं। उन्होंने कहा कि एक पारदर्शी, निर्णायक, संवेदनशील और लोकाभिमुख सरकार किस तरह से काम कर सकती है, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने यह सिद्ध करके दिखाया है।

श्री शाह ने कहा कि कालेधन के खिलाफ हमने कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद कैबिनेट की पहली ही बैठक में काले धन के खिलाफ SIT का गठन किया गया, बेनामी संपत्ति क़ानून बनाकर काले धन पर नकेल कसी गई, सिंगापुर-मॉरीशस-साइप्रस के काले-धन के रूट को बंद किया गया, डिमोनेटाईजेशन के जरिये काले धन पर कारारा प्रहार किया गया, दो लाख से अधिक शेल कंपनियों को बंद किया गया और चुनावी चंदे के लिए कैश की सीमा को भी 2000 रुपये तक सीमित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि केवल डीबीटी योजना के माध्यम से हम लगभग 59 हजार करोड़ के भ्रष्टाचार की चोरी को रोकने में सफल हुए। उन्होंने कहा कि पांच सालों में केवल डीबीटी योजना के माध्यम से देश को लगभग तीन लाख करोड़ रुपये की बचत होगी जिससे गरीब कल्याण की योजनाओं को गति मिल पायेगी।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आर्थिक सुधार के मोर्चे पर मोदी सरकार ने आशातीत सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि 2013-14 में देश की आर्थिक ग्रोथ की दर 4.7% थी जबकि हम इसे पिछले तीन साल में औसतन 7% से ऊपर लाने में सफल हुए हैं, इसी तरह ब्याज दर को भी 8 से 12% की जगह 6% तक लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है, CPI महंगाई डर को भी हम कांग्रेस सरकार के समय के 9.3% की जगह 4.5% के आसपास लाने में हम सफल हुए हैं, करेंट अकाउंट डेफिसिट भी काफी कम हुआ है, फोरेक्स रिजर्व पहली बार 400 बिलियन डॉलर के पार पहुंचा है, FDI इनफ्लो में रिकॉर्ड उछाल आया है और शेयर बाजार भी सफलता के नए मापदंड स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन साल में ही करदाताओं की संख्या 3.7 करोड़ से बढ़ कर 6.3 करोड़ हो गई है, यही बताता है कि काले धन के खिलाफ हमने कितनी कठोर कार्रवाई की है।

श्री शाह ने कहा कि केरल और पश्चिम बंगाल से काफी चिंताजनक समाचार सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि केरल में वामपंथी सरकार के गठन के बाद पिछले 6 महीने में ही हमारे 13 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में लगभग 300 जगहों पर हमारे विस्तारकों को जेल में डाला गया, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किये जा रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का गला घोटने का वीभत्स काम आजादी के बाद इतना ज्यादा कभी किसी राज्य में नहीं हुआ, जितना केरल और पश्चिम बंगाल में हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम हिंसा में यकीन नहीं रखते लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से हम इसका सही प्रत्युत्तर देंगे। उन्होंने कहा कि केरल में 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक भाजपा की केरल इकाई ने पार्टी कार्यकर्ताओं पर हो रहे हिंसक हमले के खिलाफ राज्य के गांव-गांव में जनजागृति लाने के लिए पैदल मार्च निकालने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि यदि कुछ लोगों को लगता है कि वे हिंसा के जरिये भारतीय जनता पार्टी के विकास को रोक देंगे, तो यह उनकी गलतफहमी है। उन्होंने विरोधियों को चुनौती देते हुए कहा कि हिंसा का कीचड़ भाजपा पर जितना अधिक उछाला जाएगा, कमल उतना और तेजी से खिलेगा। उन्होंने कहा कि इन कायराना हरकतों से हमें झुकाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि हमने तो आपातकाल के दौरान भी संघर्षों का सामना किया है और हम संघर्षों एवं बलिदानों में तप कर निकले हुए लोग हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे वामपंथी राजनीतिक हिंसा को देश की जनता के सामने एक्सपोज करें। उन्होंने कहा कि हम पार्टी के सिद्धांत और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ हमने जीरो टॉलरेंस का रुख इख्तियार किया है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन सालों में जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद की स्थिति पर नियंत्रण करने में हम सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को जमीन पर उतार कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान द्वारा टेरर फंडिंग पर हमारी जांच एजेंसियां रोक लगाने में सफल हुई हैं। उन्होंने कहा कि विश्व स्तर पर सभी सम्मेलनों में पाकिस्तान की भूमि से जारी आतंकवाद को एक्सपोज करने का काम किया गया है।

श्री शाह ने कहा कि इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ में विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के भाषण का उल्लेख करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि श्रीमती सुषमा स्वराज ने यूएन के फोरम से पाकिस्तान को बेनकाब करके रख दिया है। उन्होंने कहा कि देश की विदेश नीति में इन तीन सालों में आमूल-चूल परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साहसिक एवं निर्णायक फैसलों से हमारी विदेश नीति सफल हुई है।

तीन तलाक के मुद्दे पर बोलते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और साहस का परिचय देते हुए महिलाओं के समान अधिकार और पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने की पहल की जिसे देश के न्यायतंत्र ने भी सकारात्मक प्रतिसाद दिया। उन्होंने कहा कि मैं उन सभी तीन तलाक पीड़ित महिलाओं को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने न्याय के लिए संघर्ष किया और देश के करोड़ों पीड़ित महिलाओं के लिए न्याय का रास्ता आसान किया।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 1955 से देश में पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने की मांग हो रही थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार सदन में इसके लिए विधेयक लेकर आई, लोकसभा में तो यह विधेयक पास हो गया क्योंकि लोक सभा में हमारा बहुमत है लेकिन राज्य सभा में कांग्रेस ने इस बिल को गिरा देने का पाप किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राज्य सभा में पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने वाले विधेयक को गिराकर एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि वह देश के पिछड़े

वर्ग को सम्मान नहीं देना चाहती। उन्होंने कहा कि मैं इस जन-प्रतिनिधि सम्मेलन के माध्यम से देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार देश के पिछड़े वर्ग को सम्मान दिलाने के लिए कटिबद्ध है, हम 2019 से पहले उन्हें सम्मान दिलाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय सरकार जो विधेयक लेकर आई, इसके लिए मैं पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का और केंद्र सरकार का हार्दिक अभिनंदन करता हूं।

श्री शाह ने कहा कि लालबत्ती पर प्रतिबंध लगाकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक ही फैसले से देश के दो वर्गों को एक समाज में तब्दील कर दिया है, आज कोई शासक वर्ग नहीं है, सब देश के सेवक हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने न्यू इंडिया के लिए 2022 तक 6 लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प लिया है – गंदगी भारत छोड़ो, गरीबी भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, आतंकवाद भारत छोड़ो, जातिवाद भारत छोड़ो और सम्प्रदायवाद एवं तुष्टिकरण भारत छोड़ो। उन्होंने कहा कि हमें इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए।

डोकलाम मुद्दे पर बोलते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि डोकलाम के विवाद के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं कि किस तरह से इस संकट का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्र की भाजपा सरकार ने दृढ़ साहस एवं दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए कूटनीति के जरिये डोकलाम समस्या का शांति से सुगम समाधान निकालकर देश की कूटनीति को व्यापक स्तर पर प्रतिष्ठित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमने भूटान के साथ भी अपने पड़ोसी धर्म का अच्छे से निर्वहन किया। उन्होंने कहा कि डोकलाम पर भारत की भूमिका को विश्व स्तर पर स्वीकार किया गया है, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

श्री शाह ने कहा कि चीन में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन में जारी ब्रिक्स घोषणापत्र के माध्यम से हम पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी संगठनों को शामिल करके पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने में हम सफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन की सफलता से भारत, चीन, रूस और ब्राजील के बीच आपसी सहयोग बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की चीनी समकक्ष के साथ मुलाक़ात से भारत और चीन के आपसी संबंधों को भी मजबूती मिलेगी।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एवं गुजरात के विधान सभा चुनाव सन्निकट हैं। हिमाचल प्रदेश एवं गुजरात की जनता का अभूतपूर्व समर्थन एवं कार्यकर्ताओं में जोश देखने से यह निश्चित है कि हमें दोनों राज्यों में ऐतिहासिक जीत मिलने वाली है।

श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, वह न तो देश की सुरक्षा के मुद्दे पर बहस कर सकती है, न विकास के मुद्दे पर, न सकरार के निर्णय लेने की क्षमता पर और न ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के परिश्रम व विजन पर। राहुल गांधी द्वारा वंशवाद को भारत का स्वभाव बताये जाने पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि वंशवाद कांग्रेस पार्टी का स्वभाव बन गया है, यह भारत का स्वभाव कभी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमने देश से परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का अंत कर पॉलिटिक्स ऑफ़ परफॉरमेंस की शुरुआत की है - उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं मणिपुर के विधानसभा चुनाव परिणाम इसके उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस-नीत यूपीए के 10 सालों में जितना काम नहीं हुआ, उससे अधिक मोदी सरकार के तीन सालों में हुआ है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हर मोर्चे पर सफल साबित हुई है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जब केरल और पश्चिम बंगाल में हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या होती है, उन पर अत्याचार किया जाता है, जब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाया जाता है तब तो असहिष्णुता की बात नहीं की जाती लेकिन जैसे ही कोई चुनाव आता है- असहिष्णुता के मुद्दे पर जोर-शोर से चर्चा शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा कि यदि असहिष्णुता का मुद्दा उठाने में भी समानता नहीं है तो फिर असहिष्णुता का मुद्दा उठाने का भी किसी को अधिकार नहीं है।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने न्यू इंडिया का विजन देश की जनता के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 1942 से 1947 के दौरान देश के सभी लोग 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' के आह्वान पर आजादी प्राप्त करने के लिए एकजुट हो गए थे, ठीक उसी तरह से 2022 में जब देश आजादी की 75 वर्षगाँठ मना रहा होगा, न्यू इंडिया का विजन देश की 125 करोड़ जनता के लिए संकल्प का नारा बने, हमें इस दिशा में प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने न्यू इंडिया के लिए 2022 तक 6 लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प लिया है – गंदगी भारत छोड़ो, गरीबी भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, आतंकवाद भारत छोड़ो, जातिवाद भारत छोड़ो और सम्प्रदायवाद एवं तुष्टिकरण भारत छोड़ो। उन्होंने कहा कि हमें इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज हम सभी अपने सार्वजनिक जीवन में शुचिता का प्रण लें ताकि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले सभी लोग इस दिशा में आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन को उंचाई देने के लिए प्रयत्न करना हमारा दायित्व है। उन्होंने जन-प्रतिनिधियों का आह्वान करते हुए कहा कि हम सब परिश्रम की पराकाष्ठा करें और भारत माता को विश्वगुरु के पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए कृतसंकल्पित हो जाएं। ■

लोकतंत्र में जन-भागीदारी देश के विकास का आधारभूत अवयव है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 सितंबर, 2017 को नई दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में संपन्न भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के समापन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने अपने प्रेरक भाषण में कहा कि लोगों ने भाजपा के सकारात्मक दृष्टिकोण के प्रति भरोसा जताया है। पार्टी अब भारतीय राजनीति का केंद्र बिन्दु बन गई है।
हम अपने सुधी पाठकों के लिए प्रधानमंत्री के भाषण के कुछ अंश प्रकाशित कर रहे हैं:

हम सिर्फ एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नहीं हैं बल्कि देश के जन-सामान्य की आशाओं एवं आकांक्षाओं के केंद्र बिंदु बने हैं।

- भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
- भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में रहते हुए संगठन की शक्ति को जनता और सरकार के बीच सेतु के रूप में प्रतिस्थापित करके दिखाया है।
- सत्ता में रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का संगठन जितना सक्रिय है, उतना कोई और दल देश में सक्रिय नहीं है। संगठन हमारे लिए चुनाव जीतने की मशीन नहीं बल्कि जनता को सरकार से जोड़ने का एक उपक्रम है और सत्ता हमारे लिए जनता की सेवा का एक माध्यम।
- विपक्ष का दायित्व मुद्दों पर आधारित राजनीति कर जन-जागरण करने का होता है लेकिन दुर्भाग्य से विपक्ष अपने मुद्दों से हट कर छींटाकशी, ओछे आरोप और हल्की बातों पर उतर आया है। जब वे सत्ता में थे तो उनके लिए सत्ता उपभोग का एक माध्यम थी और इसलिए उनके मन में जनसेवा और लोकतंत्र का भाव जागता ही नहीं है।
- लोकतंत्र में जन-भागीदारी देश के विकास का आधारभूत अवयव है।
- भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जन-प्रतिनिधि सरकार की योजनाओं को किसानों तक ले जाएं, उनसे ग्राम-स्तर पर समस्याओं पर विचार-विमर्श करें और 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी भूमिका निभाएं।
- 'न्यू इंडिया' देश के हर नागरिक का संकल्प होना चाहिए। यदि हम इस संकल्प को लेकर जन-भागीदारी द्वारा आगे बढ़ें तो गरीबी की लड़ाई को लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है।
- गरीबों के सशक्तिकरण पर बल देना है और मध्यम वर्ग पर से आर्थिक बोझ को कम करना है ताकि हम गरीबी से जंग जीत सकें।
- दुनिया भर में भारत की एक अलग छवि बनी है, भारत के प्रति विश्वास का वातावरण बना है और दुनिया के देश आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई को समर्थन दे रहे हैं।
- हमने चीन के साथ भी शांति के साथ समस्या का समाधान किया है। आज हम ऐसे स्थान पर खड़े हैं, जहां भारत यदि कोई संकल्प कर ले तो उसे पूरा किया जा सकता है।
- विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, अनाप-शनाप भाषा का प्रयोग इसलिए हो रहा है क्योंकि हम हर कदम पर सफल हो रहे हैं और उनके लिए बात करने को कुछ भी नहीं है।
- आगामी 31 अक्टूबर को को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है, इस अवसर पर पार्टी ने 'रन फॉर यूनिटी' का आयोजन किया है, यह भव्य कार्यक्रम कोटि जन जन का कार्यक्रम बनना चाहिए।
- चुनाव में हम सफल हो, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम चुनाव के बाद सफल हों और लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरें।
- इन्द्रधनुष कार्यक्रम को हमें सफल बनाना है ताकि देश का हर बच्चा स्वस्थ और देश के विकास में अपनी भूमिका अदा कर सके।
- कैसे एक सिलिंडर लोगों की जिंदगी में बदलाव का कैटेलिक एजेंट बन सकता है, यह प्रधानमंत्री उज्जवला योजना और एलपीजी पंचायत कार्यक्रम ने सिद्ध करके दिखाया है।
- प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के माध्यम से केंद्र सरकार देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी मुफ्त में बिजली का कनेक्शन मुहैया करायेगी। ■

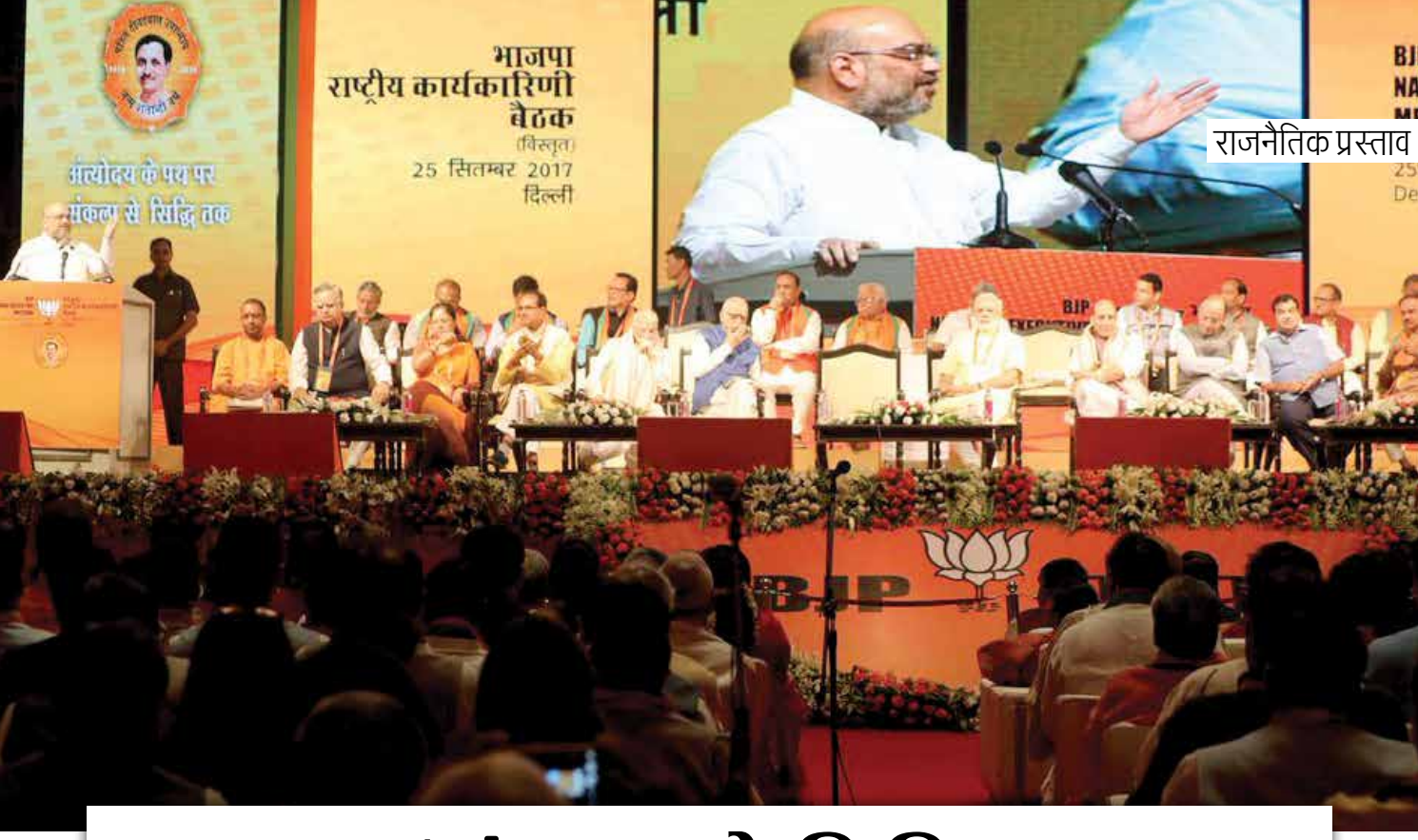

'संकल्प से सिद्धि'
जनांदोलन का आह्वान

गत 25 सितंबर, 2017 को नई दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव श्री भूपेंद्र यादव ने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने इसका अनुमोदन किया।
हम अपने सुधी पाठकों के लिए राजनीतिक प्रस्ताव के प्रमुख अंश प्रकाशित कर रहे हैं:

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकासोन्मुख नीतियों की वजह से उनके प्रति देश में समर्थन और विश्वास में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपानीत केंद्र सरकार की नीतियां दूरदर्शी, लोक कल्याण को समर्पित एवं आर्थिक मजबूती के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर भारत की साख को मजबूत करने वाली हैं। आतंकवाद व अलगाववाद पर सख्ती, कुशल विदेश नीति, महिलाओं के गरिमापूर्ण जीवन के अवसरों में वृद्धि, गरीब कल्याणकारी नीति व वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर सरकार के प्रति जनमानस में विश्वास मजबूत हुआ है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके नेतृत्व में राष्ट्र के चतुर्मुखी विकास को समर्पित नीतियों के द्वारा अर्जित उपलब्धियों पर बधाई देती है। इन अनेक उपलब्धियों में प्रतिनिधिक रूप में कुछ उपलब्धियां निम्नलिखित हैं-

पारदर्शी अर्थतंत्र की बुनियाद

भ्रष्टाचार और कालेधन के खिलाफ केंद्र सरकार ने जनता को दिए अपने वचन को सिद्ध किया है। विमुद्रीकरण को लेकर मिला जनसमर्थन इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। इस एक निर्णय ने कालाबाजारी और कालाधन रखने वालों की कमर तोड़ दी है। इस निर्णय से देश में पारदर्शी अर्थतंत्र की बुनियाद मजबूत करने की दिशा

में अभूतपूर्व सफलता मिली है, ईमानदारी से कारोबार करने वालों के लिए अवसर सुगम हुए हैं। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा, गैस सब्सिडी, पेंशन, स्कॉलरशिप इत्यादि का सीधे डिजिटल माध्यम से नकद हस्तांतरण करके करोड़ों लाभार्थियों के जीवन में पारदर्शी व्यवस्था से सुगमता लाई गयी है। इस व्यवस्थागत परिवर्तन का परिणाम है कि देश में व्यक्तिगत टैक्स देने वालों की संख्या में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई है, डिजिटल लेन–देन दोगुना हुआ है एवं बड़े नोटों के नकद प्रचलन में भी पर्याप्त कमी आई है। केंद्र सरकार की नीतियों से सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को सम्मान मिलने लगा है। देश में पारदर्शी अर्थव्यवस्था को लागू कराने के लिए केंद्र सरकार बधाई के योग्य है।

1. जीएसटी: लागू हुआ 'एक राष्ट्र एक कर'

भाजपानीत केंद्र सरकार ने देश में "वन नेशन, वन टैक्स" की लंबे समय से चल रही मांग को पूरा किया है। विमुद्रीकरण के बाद अप्रत्यक्ष करों को लेकर आर्थिक सुधारों की दिशा में यह दूसरा ऐतिहासिक कदम सरकार द्वारा उठाया गया है। जीएसटी लागू होने से व्यापार में सुगमता को लेकर व्यापारी वर्ग को होने वाली समस्याओं को समाप्त किया गया है। दैनिक उपयोग की तमाम वस्तुओं पर लगने वाले करों का बोझ भी कम हुआ है। इस टैक्स के लागू होने के प्राम्भिक दौर में जनता और व्यापारियों को होने वाली दिक्कतों का समाधान सरकार लगातार कर रही है। जीएसटी लागू होने के बाद संघीय ढांचे के अनुरूप सभी प्रदेशों को विश्वास में लेते हुए सर्वसम्मति से जीएसटी लागू कराना केंद्र सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि है। प्रत्येक महीने जीएसटी काउंसिल की बैठक के माध्यम से जनता के प्रति विकासोन्मुख निर्णय लेने का आदर्श भी सिद्ध किया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करती है।

2. आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ ठोस नीति

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनने के बाद से ही सरकार की आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ "जीरो टॉलरेंस" ठोस नीति रही है। सरकार इसी नीति पर चलते हुए आतंकवादी तत्वों एवं उनके सहयोगियों के खिलाफ सख्ती से निपट रही है। हाल के दिनों में सरकार द्वारा आतंकवाद के खिलाफ जिस ढंग से सीमाओं पर सख्त कदम उठाये गये हैं, वह देश के सामने है। पिछले 6 महीने में बड़ी संख्या में आतंकियों को ढेर किया गया है, जिससे आतंकी गतिविधियों में शामिल तत्वों का मनोबल गिरा है। सुरक्षा बलों ने इस पूरे मामले में जिस संवेदनशीलता का परिचय दिया है, वह उल्लेखनीय और सराहनीय है। जम्मू-कश्मीर के आम लोगों ने सरकार की कार्यपद्धति की सराहना की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू-कश्मीर में बाढ़ के संकट का समाधान एवं विकास योजनाओं में केंद्र सरकार के सकारात्मक योगदान को प्राथमिकता दी है। जम्मू-कश्मीर के 80 हज़ार करोड़ का विकास पैकेज, दो एम्स, आईआईएम, आईआईटी, पांच मेडिकल कॉलेज एवं इंजीनियरिंग कॉलेज के माध्यम से विकास को तेज गति दी है। सरकार के इन योजनाओं से जम्मू-कश्मीर में विश्वास का माहौल बना है। आतंकवाद से निपटने में आतंकियों के खिलाफ सख्ती और आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे आम लोगों के प्रति संवेदनशीलता के बीच सन्तुलन बनाने का अभूतपूर्व कार्य किया है।

वैश्विक पटल पर भी आतंकवाद के विषय को मजबूत ढंग से रखने में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभूतपूर्व सफलता दिलाई है। अलगाववादियों को विदेशों से मिलने वाली मदद के अवैध स्रोतों के आर्थिक तंत्र एवं हवाला कारोबार की कड़ियों पर सरकार द्वारा की गयी व्यापक कार्यवाही सराहनीय है.वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली को देखते हुए आम जनता के बीच भी यह धारणा बनी है कि आतंकवाद के खिलाफ यह सरकार कड़े से कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटने वाली है। सरकार द्वारा विकास से जुड़े मुद्दों पर सामानांतर कार्य

किया गया है। वैश्विक पटल भी आतंकवाद के विषय को बहस के केंद्र लाने, पाकिस्तान को वैश्विक पटल पर अलग-थलग करने और हिजबुल मुजाहीद्दीन जैसे आतंकी संगठन की असलियत को सामने लाने के लिए एवं विश्व जनमत को उनके खिलाफ एकजुट करने के लिए यह सरकार बधाई की पात्र है।

4. महिलाओं के समानता एवं गरिमापूर्ण जीवन के अवसरों को बढ़ाना

राष्ट्रीय कार्यकारिणी केंद्र सरकार महिलाओं के जीवन में समानता एवं गरिमापूर्ण जीवन के अवसरों में सुचारू रूप से बढ़ाने के लिए उसकी प्रतिबद्धता हेतु बधाई देती है। सरकार द्वारा महिलाओं की हितों की दिशाओं में बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, सुकन्या समृद्धि योजना एवं उज्जवला योजना के माध्यम से तीन करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभार्थी बनाया गया है। देश में बढ़ते हुए लिंगानुपात को समान

करना, बेटियों के प्रति संकीर्ण सामाजिक दृष्टिकोण का उन्मूलन एवं बेटियों को शिक्षित बनाने में सरकार के प्रयास सराहनीय हैं। कामकाजी महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर अधिक सुरक्षित माहौल हेतु कानूनों में परिवर्तन एवं मातृत्व सुरक्षा को महत्व देने का कार्य सरकार द्वारा किया गया है। सरकार की मुद्रा योजना का लाभ भी महिलाओं द्वारा उठाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तीन तलाक विषय पर केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से न्यायपूर्ण पक्ष रखा, कार्यकारिणी उसका स्वागत करती है। तीन तलाक जैसी कु-प्रथा की वजह से लैंगिक असमानता और संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था। इस संदर्भ में केंद्र सरकार का पक्ष स्पष्ट था कि समानता संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है और बदला नहीं जा सकता है। इस फैसले का समाज के हर वर्ग की महिलाओं सहित मुस्लिम महिलाओं ने भी स्वागत किया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी देश की करोड़ों महिलाओं की ओर से महिलाओं के सम्मान एवं समर्थन में इस साहसपूर्ण कदम के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करती है।

5. किसानों के हितों की दिशा में सरकार के कार्य

सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के विषय को जमीनी स्तर तक ले जाने का बड़ा सन्देश दिया गया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड एवं किसान फसल बीमा योजना से खेती में उत्पादन वृद्धि एवं अनिश्चतताओं को दूर करने में सफलता मिली है। प्रधानमंत्री फसल बीमा में प्रीमियम बहुत कम रखा गया है एवं आपदा क्षेत्रों को भी विस्तृत किया गया है जिससे अधिकाधिक क्षतिपूर्ति हो सके। वर्ष 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री सिचांई योजना के तहत 5 वर्षों में पचास हज़ार करोड़ निवेश का प्रावधान किया गया है। सरकार द्वारा जारी की गई ग्रामीण क्षेत्र की आधारभूत संरचनाओं की योजनाओं से किसानो के जीवन में परिवर्तन आया है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार द्वारा संकल्प पूर्वक किये जा रहे प्रयासों से प्रति अपना आभार व्यक्त करती है।

6. युवा शक्ति से ही राष्ट्र विकास

राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस वर्ष को स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण के 125 वर्ष पूरा होने के कारण युवाओं के लिए प्रेरणादायक वर्ष मानती है। देश निर्माण में युवाओं की भूमिका के लिए ना केवल केंद्र सरकार ने समयानुकूल नयी शिक्षा नीति के लिए व्यापक विमर्श शुरू किया है बल्कि उसके साथ–साथ नए स्वरोजगार के अवसरों की भी उपलब्धता कराई है। युवाओं के समन्वित विकास के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, कौशल विकास एवं उधामिता की राष्ट्रीय नीति, प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना को शुरू किया गया.मुद्रा योजना के साथ स्टार्ट-अप इंडिया एवं स्टैंड-अप इंडिया के द्वारा देश की 125 लाख बैंक शाखाओं को युवाओ के रोजगार निर्माण के लिए ऋण अभियान शुरू किया है और इसमे कम से कम एक दलित, आदिवासी व महिला उद्यमी को जोड़ा गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सरकार के द्वारा युवाओं के समन्वित विकास के लिए की जा रहे पहल पर बधाई देती है।

7. डोकलाम पर शांतिपूर्ण समाधान

इस वर्ष जून में भारत और चीन के बीच उत्पन्न हुए डोकलाम विवाद को शान्तिपूर्ण तरीके से राजनयिक बातचीत के द्वारा सुलझाने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी सरकार को बधाई देती है। यह घटनाक्रम राजनीतिक परिपक्वता और कूटनीति की विजय का परिचायक है। इस मामले पर देश के नेतृत्व ने जिस कुशलता तथा धैर्यसंयम और दृढ़ता का परिचय दिया उनसे राष्ट्र के हितों की रक्षा तो हुई हीसाथ ही विश्व में भारत का सम्मान और भी बढ़ा है। इस प्रकरण के दौरान भूटान से लगातार परामर्श और समन्वय पड़ोसी मित्र देश के हितों के प्रति भारत की संवेदनशीलता तथा सरकार की ''सबसे पहले पड़ोसी'' (Neighbourhood First) की नीति भली-भांति दर्शाते हैं।

8. ब्रिक्स में दिखी भारत की मजबूती

BRICS शिखर सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा विश्व की चुनौतियों का मिलजुलकर सामना करने के लिए दिये गये 10 सूत्रीय सुझाव एक और रचनात्मक पहल है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस पहल का दुनिया के देशों द्वारा विकास की अवधाणा पर एक सकारात्मक प्रयास के रूप में स्वागत किया गया। चीन के शियामिन (Xiamen) में हुए BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सकारात्मक बातचीत का भी परिषद स्वागत करती है। यह महत्वपूर्ण है कि दोनों नेताओं ने उनके बीच अस्ताना, कजाख़स्तान में

यह धारणा बनी है कि आतंकवाद के खिलाफ यह सरकार कड़े से कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटने वाली है। सरकार द्वारा विकास से जुड़े मुद्दों पर सामानांतर कार्य किया गया है। वैश्विक पटल भी आतंकवाद के विषय को बहस के केंद्र लाने, पाकिस्तान को वैश्विक पटल पर अलग-थलग करने और हिजबुल मुजाहीद्दीन जैसे आतंकी संगठन की असलियत को सामने लाने के लिए एवं विश्व जनमत को उनके खिलाफ एकजुट करने के लिए यह सरकार बधाई की पात्र है।

हुई इस सहमति को दोहराया कि भारत और चीन के बीच अच्छे संबंध विश्व में स्थिरता के लिए आवश्यक हैं। BRICS शिखर सम्मेलन से जारी किये गये घोषणा पत्र में आतंकवाद को जो प्रमुख स्थान मिला है और जिस प्रकार से भारत के पड़ोस में सक्रिय दुर्दान्त आतंकवादी समूहों जैसे लश्कर-ए-तोएबा, तालिबान, जैश-ए-मुहम्मद व हक्कानी समूह आदि की कड़ी निन्दा की गयी है वह आतंकवाद पर वैश्विक सहमति बनाने में सरकार के अथक कूटनीतिक प्रयासों की सफलता का एक और प्रमाण है।

9. अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में संवेदनशीलता को प्राथमिकता

भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने कूटनीति में मानवीय संवेदनशीलता को प्राथमिकता देकर दुनिया में अच्छे सम्बंधो को मजबूत किया है। पड़ोसी देशों के साथ ही नेपाल की भूकंप की

राष्ट्रीय कार्यकारिणी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनांदोलन के रूप शुरु किये गये "संकल्प से सिद्धि" कार्यक्रम का स्वागत करते हुए वर्ष 2022 तक गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद, साम्प्रदायिकता से मुक्त स्वच्छ भारत बनाने का संकल्प लेती है। पार्टी देश के 125 करोड़ लोगों से आह्वान करती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कदम से कदम मिलकर न्यू इंडिया के संकल्प के साथ आगे बढ़े।

त्रासदी में, मालद्वीप में पानी के संकट तथा म्यामांर में स्वाईन फ्लू के संकट पर भारत ने पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्तों को जिम्मेदारी से निभाया है। बंगलादेश के रोहिंग्या शरणार्थीयों को सरकार द्वारा आगे बढ़कर राहत सामग्री भिजवाई है इसके साथ ही सरकार ने अपने 125 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा का भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी जिम्मेदारी निभाई है। इसमे यमन में फसे भारतीय नागरिकों का संकट हो, मध्यपूर्व देश से केरल की नर्सों की रिहाई हो, अफगानिस्तान से अलेक्स प्रेम कुमार की रिहाई हो, यमन से फादर टॉम की रिहाई हो, सरकार ने हर नागरिक की व्यक्तिगत एवं सामूहिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी केंद्र सरकार द्वारा तत्परतापूर्वक किये गये सफल कूटनीतिक प्रयासों के लिए बधाई देती है।

10. आधारभूत संरचनाओं को मजबूती

राष्ट्रीय कार्यकारिणी भाजपानीत केंद्र सरकार द्वारा देश की आधारभूत संरचना के विकास के लिए उठाए गए नए कदमों और पुराने कार्यों को पूरा कर देश को समर्पित करने के लिए बधाई देती है। इस क्रम में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना के अंतिम चरण को पूरा कर देश को समर्पित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देती है। साथ ही भारत-जापान सहयोग से देश में "बुलेट-ट्रेन" की नींव रखने के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कार्य कर रही केंद्र सरकार बधाई के योग्य है।

11. हिंसा लोकतंत्र के लिए अभिशाप

देश में वैचारिक हिंसा तथा संकीर्णता को समाप्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश की जनता को दिए गये भरोसे का स्वागत करती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का स्पष्ट मत है कि केरल, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल में पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जिस ढंग से विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा राजनीतिक हिंसा की जा रही है, वह लोकतंत्र में निंदनीय है। केरल में विगत चौदह माह में पार्टी के 14 कार्यकर्ताओं का निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी इसकी कड़ी निंदा करती है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी पत्रकारों पर किये जा रहे हिंसा एवं हत्या की भी पुरजोर तरीके से निंदा करती है।

12. पिछड़े वर्ग को संवैधानिक अधिकार हेतु संकल्प

भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य "सबका साथ, सबका विकास" के उद्देश्यों को प्राप्त करना है। इस क्रम में सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग की संवैधानिक मान्यता का प्रश्न दशकों से लंबित था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का निर्णय लिया। लोकसभा से यह संशोधन विधेयक पारित भी हुआ। लेकिन राज्यसभा में कांग्रेस के विरोध की वजह से यह प्रस्ताव लागू नहीं हो सका है। भाजपा पूरी प्रतिबद्धता के साथ इसे लागू कराने का संकल्प लेती है और कांग्रेस द्वारा राज्यसभा में पैदा किए गए पिछड़ा विरोधी गतिरोध की निंदा करती है।

13. पंडित दीन दयाल जन्मशताब्दी वर्ष का संकल्प

भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीन दयाल जन्म शताब्दी वर्ष (25 सितंबर 2016- 25 सितंबर 2017) को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाया है। पार्टी की केंद्र व राज्य सरकारों ने गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से शोषित एवं वंचित वर्ग को जीने का आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से उन्नत किया है।

दीनदयाल जन्मशताब्दी वर्ष में पार्टी के जनाधार, बूथ रचना को मजबूत करने, पार्टी के संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण, वैचारिक आधार के विस्तार एवं पार्टी के कार्यप्रणाली में गुणात्मक विस्तार हेतु अखिल भारतीय अध्यक्षीय प्रवास माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह द्वारा किया गया। पार्टी के कार्य विस्तार के लिए विस्तारक योजना का प्रारंभ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बंगाल के नक्सलवाड़ी दौरे के साथ प्रारंभ हुआ। पार्टी के लिए संतोष का विषय है कि सुदूर लद्दाख से लेकर लक्षद्वीप तक 4 लाख के करीब विस्तारक अल्पकालिक प्रवास के लिए गये और 4 हज़ार से अधिक विस्तारक दीर्घकालिक प्रवास के लिए गये।

भारतीय जनता पार्टी के बूथ रचना को मजबूत करने के लिए इन विस्तारकों द्वारा बूथों पर समाज के सभी वर्गों का पार्टी में समावेश, बूथ समिति की रचना तथा बूथ के छह कार्यप्रणाली को स्थाई बनाने पर जोड़ दिया गया, जिससे 'सशक्त भाजपा-समर्थ भाजपा' की परिकल्पना को आगे बढ़ाने में पार्टी को मजबूती मिली है।

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा किये गये संगठानात्मक प्रवास से पार्टी की विभागों एवं प्रकल्पों की परिकल्पना, कार्यालय निर्माण, समाज के प्रबुद्ध वर्ग से बातचीत, कोर समिति की संगठनात्मक निर्णय की प्रणाली, पार्टी की सरकारों की कार्यप्रणाली की दिशा, जनसंघ के समय के कार्यकर्ता का सम्मान, पार्टी के निर्वाचित सदस्यों की भूमिका तथा वैचारिक प्रशिक्षण के लिए आवश्यक तंत्र का निर्माण किया गया। यह प्रवास पार्टी के संगठनात्मक एवं गुणात्मक सुदृढ़ता में मील का पत्थर सिद्ध हो रहा है।

पार्टी दीनदयाल जन्मशताब्दी वर्ष में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अखिल भारतीय प्रवास के माध्यम से मिले मजबूत आधार को भविष्य में पार्टी के काम का आधार बनाकर उसे सशक्त करेगा।

14. न्यू इण्डिया: संकल्प से सिद्धि

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने तक "न्यू इण्डिया" का संकल्प प्रस्तुत किया है। संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत देश को 2022 तक न्यू इण्डिया के लक्ष्यों को संकल्प के रूप में देश के समक्ष रखा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का यह स्पष्ट मत है कि 125 करोड़ देशवासी इस संकल्प को अपना व्यक्तिगत संकल्प बनायेंगे तो न्यू इण्डिया बनने से कोई रोक नहीं सकता। न्यू इंडिया में छः संकल्प अंतर्निहित हैं।

गरीबी से मुक्त भारत:

न्यू इण्डिया के तहत यह संकल्प लिया गया है कि 2022 तक हम भारत को गरीबी से मुक्त एक ऐसा देश बनायेंगे जहां सबके पास आवास हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं हों, स्व-रोजगार के अवसर हों। इस संकल्प के आलोक में केंद्र सरकार द्वारा लोक कल्याण की कई योजनायें संचालित हैं और अन्त्योदय की अवधारणा के अनुरूप आम लोगों तक पहुंच रही हैं।

स्वच्छ भारत:

सुंदर समाज और समृद्ध देश की पहचान स्वच्छता भी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 'स्वच्छ भारत अभियान" को जनांदोलन का रूप देते हुए इसे व्यक्ति के दायित्वबोध से जोड़ा है। न्यू इण्डिया में भारत स्वच्छ हो और समाज से गंदगी को समाप्त किया जा चुका हो, यह संकल्प लेते हैं।

आतंकवाद से मुक्त:

आतंकवाद आज विश्व के लिए एक खतरा है। केंद्र सरकार आतंकवाद के खिलाफ सख्त है। न्यू इण्डिया के अंतर्गत आतंकवाद मुक्त भारत का संकल्प लेते हैं।

जातिवाद मुक्त भारत:

सामजिक न्याय के मूल सिद्धांतों पर चलते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने न्यू इण्डिया में देश को सामाजिक विषमता से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया है। न्यू इण्डिया में समता मूलक समाज के निर्माण से मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लक्ष्यों को प्राप्त करना है।

सम्प्रदायवाद से मुक्त भारत:

समाज में साम्प्रदायिक सद्भाव हो और समरसता से परिपूर्ण समाज बने, यह न्यू इण्डिया के निर्माण में हमारा प्रमुख संकल्प है।

भ्रष्टाचार से मुक्त भारत:

माननीय प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टचार के समूल नाश के लिए ऐतिहासिक कदम उठाये हैं। हमारा संकल्प है कि 2022 में हम देश को पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था का निर्माण करने में सफल होंगे।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखे गये न्यू इण्डिया के संकल्पों का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अभिन्दन करती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनांदोलन के रूप शुरू किये गये "संकल्प से सिद्धि" कार्यक्रम का स्वागत करते हुए वर्ष 2022 तक गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद, साम्प्रदायिकता से मुक्त स्वच्छ भारत बनाने का संकल्प लेती है। पार्टी देश के 125 करोड़ लोगों से आह्वान करती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कदम से कदम मिलकर न्यू इंडिया के संकल्प के साथ आगे बढ़े। ■

झारखंड के विकास के लिए अहर्निश कार्य कर रही है भाजपा सरकार: अमित शाह

पूर्वी भारत में विकास तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज तक केंद्र में कांग्रेस और उनके सहयोगियों की जो सरकारें रहीं, उन्होंने देश के पूर्वी हिस्से के विकास की अनदेखी की।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 16 सितंबर को झारखंड की भाजपा सरकार द्वारा रांची के हरमू मैदान में आयोजित 'गरीब कल्याण मेला' कार्यक्रम में भाग लिया और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के बीच चेक, प्रतीक चिह्न और उपादानों का वितरण किया।

इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार और श्री रघुबर दास के नेतृत्व में राज्य की भाजपा सरकार झारखंड के विकास के लिए अहर्निश कार्य कर रही है।

श्री शाह ने कहा कि गरीब कल्याण मेला कार्यक्रम के स्वरूप को देखकर मुझे सच्चे अर्थों में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते सुकून और शांति की सुखद अनुभूति हो रही है। उन्होंने कहा कि 2014 के लोक सभा चुनाव के दौरान ही श्री नरेन्द्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कई बार कहा था कि देश का पूर्वी हिस्सा पश्चिमी हिस्से की तुलना में विकास से महरूम रह गया है और यदि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो देश के पूर्वी क्षेत्रों का विकास करके एक संपूर्ण विकसित भारत बनाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज तीन साल बाद मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि पूर्वी भारत में विकास तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज तक केंद्र में कांग्रेस और उनके सहयोगियों की जो सरकारें रहीं, उन्होंने देश के पूर्वी हिस्से के विकास की अनदेखी की। उन्होंने कहा कि यदि केवल झारखंड की बात की जाय तो सिर्फ खदानों की ई-नीलामी से राज्य को लगभग 1,17,000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त मिनरल एरिया वेलफेयर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से राज्य के अलग-अलग जिले में आदिवासी भाइयों के विकास के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपये झारखंड को प्राप्त होंगे।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि अलग झारखंड राज्य की मांग वर्षों से चल रही थी। इस मांग को लेकर कई आंदोलन भी हुए, लेकिन मैं झारखंडवासियों को याद दिलाना चाहता हूं कि अलग झारखंड राज्य की मांग को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। उन्होंने राज्य की जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि

'सेवा दिवस' कार्यक्रम, अरगोड़ा, रांची (झारखंड)

'स्वच्छता का आंदोलन जन आंदोलन बनता जा रहा है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 17 सितंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित 'सेवा दिवस' अभियान के तहत अरगोड़ा, रांची (झारखंड) में स्वच्छता कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर आयोजित एक जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कभी भी अपना जन्मदिन नहीं मनाते, लेकिन उनका जीवन हमेशा राष्ट्र की सेवा में समर्पित रहा है, इसलिए उनके जन्मदिन को पूरा देश 'सेवा दिवस' के रूप में मनाये, इस प्रकार की परंपरा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है।

उन्होंने कहा कि आज इस अवसर पर मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से प्रभु चरणों में वंदना करता हूं कि ईश्वर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को दीर्घायु बनाएं, उन्हें स्वस्थ रखें और प्रभु की प्रेरणा से उन्होंने जिन-जिन जन अभियानों की शुरुआत की है, उसे देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में उन्हें सफलता मिले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और देश की जनता द्वारा अनेक प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अलग-अलग प्रकार के सेवा प्रकल्पों को आगे ले जाया जा रहा है। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन को मनाने का इससे बड़ा कोई और अच्छा रास्ता नहीं हो सकता। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तभी से उन्होंने स्वच्छता के कार्य को आगे बढ़ाना शुरू किया और प्रधानमंत्री बनने के बाद फिर से एक बार स्वच्छता के संस्कार को पुनर्जीवित करने का काम देश भर में आगे बढ़ा रहे हैं।

विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि कई बार विपक्ष के कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि स्वच्छता कहां दिखाई देती है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि यह एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन आज जब कोई सड़क पर कचरा फेंकता है तो एक छोटा बच्चा भी कचरा फेंकने वाले को नसीहत देते हुए कहता है कि कचरे को डस्टबिन में डालिए। यह बदलाव आज समाज के अंदर आया है। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 सालों में जितने भी लोग शासन में आये, उनमें से किसी का ध्यान स्वच्छता की ओर नहीं गया। उन्होंने कहा कि केवल सरकार ही समाज की समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकती, जब तक जन सामान्य उन समस्याओं से नहीं जुड़ता है, तब तक सामाजिक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने स्वच्छता के आंदोलन को सरकार के आंदोलन की जगह जन-आंदोलन बनाने में सफलता प्राप्त की है। यह जन-आंदोलन ही देश को स्वच्छ बनाने में सफल होगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के अभियान को जन आंदोलन बनाने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को जाता है।

श्री शाह ने कहा कि महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र को जो 'स्वच्छता ही सेवा है' का जो सूत्र दिया है, देश में स्वच्छता के संस्कार को

पुनर्जीवित करने के लिए जो मिशन चलाया है, यह 'सेवा दिवस' उसे गति देने का एक माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से स्वच्छता को प्रधानता दी है, ब्लॉक से लेकर राज्य सरकार तक, हर जगह बजट का आवंटन करके स्वच्छता को गति दी है, नीति आयोग जिस तरह से कचरों को परिष्कृत करने वाली नीतियां बनाने लगी है, उससे स्वच्छता का आंदोलन जन आंदोलन बनता जा रहा है।

झारखंड को बनाने का काम अटल जी ने किया, इसे संवारने और विकसित करने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी करेंगे। श्री शाह ने कहा कि आज से पहले विकास के विभिन्न मापदंडों के आधार पर यदि देश के राज्यों की सूची देखी जाती थी तो झारखंड मध्य में या नीचे मिलता था, लेकिन आज यदि इस सूची को देखा जाय तो 8.6% के विकास दर के साथ झारखंड गुजरात के बाद दूसरे स्थान पर काबिज है। उन्होंने कहा कि एक सरकार जो समान विकास और गरीब कल्याण में यकीन रखती है, अंत्योदय के सिद्धांतों पर चलती है और पारदर्शी एवं निर्णायक तरीके से काम करती है तो केवल 1000 दिनों में कैसे परिणाम आ सकते हैं, यह झारखंड की रघुबर सरकार ने करके दिखाया है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आज इस गरीब कल्याण मेले के माध्यम से विभिन्न योजनाओं में राज्य के 46,000 लाभार्थियों को लगभग 340 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियां बांटी जाएंगी। उन्होंने कहा कि यह अकेला मेला नहीं है, बल्कि इस तरह के कई गरीब कल्याण मेलों की पहल झारखंड की रघुबर सरकार ने की है। उन्होंने कहा कि झारखंड की भाजपा सरकार ने 1000 दिन पूरे होने पर गरीब कल्याण मेले को आयोजित करने की जो शुरुआत की है, यही बताता है कि रघुबर सरकार का लक्ष्य क्या है। उन्होंने कहा कि झारखंड पहले एक समृद्ध राज्य तो था, लेकिन राज्य के निवासी गरीब थे लेकिन राज्य में भाजपा की रघुबर सरकार आने के बाद से राज्य के साथ-साथ राज्य के लोग भी गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनेक योजनाओं के माध्यम से राज्य की भाजपा सरकार झारखंड के गरीब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बताये हुए अंत्योदय एवं गरीब कल्याण के रास्ते पर चलते हुए गरीबों के उत्थान के लिए अनेक योजनायें लेकर आई है। उन्होंने कहा कि तीन ही साल में 2.8 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाओं को गैस सिलिंडर देने का काम पूरा कर लिया है। मुद्रा योजना से देश के 7.64 करोड़ से अधिक युवा लाभान्वित हुए हैं और विभिन्न बीमा योजनाओं से देश के गरीब से गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवच देने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि तीन साल में साढ़े चार करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण करके गांव की गरीब महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 70 साल बाद भी बिजली से वंचित देश के 18 हजार से अधिक गांवों में से 13 हजार से अधिक गांवों में बिजली पहुंचाने का काम पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि 2018 तक हर गांव में और 2022 तक देश के हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार पर 10 सालों में लगभग 12 लाख करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लेकिन विगत तीन साल से अधिक समय से केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन तीन सालों में हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा पाए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार प्रमाणिकता के साथ काम कर रही है।

श्री शाह ने कहा कि गरीब सरकार के पास आये, इसके बदले रघुबर जी ने गरीब कल्याण मेले के माध्यम से सरकार को गरीब के पास ले जाने का नया विचार झारखंड में शुरू किया है। यह बहुत अच्छी शुरुआत है और मैं इसके लिए श्री रघुबर दास को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने हर 15 दिन में देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, आदिवासी, युवा एवं महिलाओं के लिए शुरू की है। मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई 106 गरीब - कल्याण योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री

नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार झारखंड के विकास के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार झारखंड को जितनी सहायता देती थी, उसकी तुलना में मोदी सरकार ने झारखंड को लगभग तीन गुना ज्यादा दिया है।

राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अमेरिका जाकर पूछते हैं कि मोदी सरकार ने तीन साल में क्या किया है, हमने तो अपने तीन साल का हिसाब दे दिया है, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस के 50 सालों का हिसाब देश की जनता को नहीं दे रहे। ■

भारत और जापान के बीच 15 समझौतों पर हस्ताक्षर

जापानी प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे की दो दिवसीय भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 14 सितंबर को पंद्रह समझौते हुए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। भारत और जापान ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए नागर विमानन, कारोबार, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल समेत विभिन्न क्षेत्रों में 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किये।

इसके बाद साझा बयान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री श्री शिंजो एबी को सबसे अच्छा मित्र बताया। वहीं, जापानी प्रधानमंत्री ने भारत के डिजिटल इंडिया व मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के प्रति अपना समर्थन जताया। श्री मोदी ने प्रेस वक्तव्य में 14 सितंबर को कहा कि आज सुबह हम दोनों ने मिल कर जापान के सहयोग से बनाए जा रहे मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवेज प्रोजेक्ट का भूमिपूजन किया। यह एक बहुत बड़ा क़दम है। यह सिर्फ़ हाई स्पीड रेल की शुरुआत नहीं है। भविष्य में हमारी आवश्यकताओं को देखते हुए मैं इस नई रेलवे फिलॉसोफी को नए भारत के निर्माण की जीवनरेखा मानता हूं। भारत की अबाध प्रगति का संपर्क अब और भी तेज गति से जुड़ गया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपसी विश्वास और भरोसा,

एक दूसरे के हितों और चिंताओं की समझ, और उच्च स्तरीय सतत संपर्क, यह भारत जापान संबंधों की ख़ासियत हैं। हमारी स्पेशल स्ट्रेटेजिक और वैश्विक साझेदारी का दायरा सिर्फ़ द्विपक्षीय या क्षेत्रीय स्तर तक ही सीमित नहीं है। वैश्विक मुद्दों पर भी हमारा सहयोग घनिष्ठ है। पिछले वर्ष मेरी जापान यात्रा के समय हमने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया था। इसके रैटिफिकेशन के लिए मैं जापान के जनमानस, जापान की संसद, और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री आबे का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। क्लीन एनर्जी और जलवायु परिवर्तन के विषय पर हमारे सहयोग के लिए इस समझौते ने एक नया अध्याय जोड़ा है।

श्री मोदी ने कहा कि 2016-17 में भारत में जापान से 4.7 अरब डॉलर का निवेश हुआ है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 80 प्रतिशत अधिक है। अब जापान भारत में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है। यह साफ़ दर्शाता है कि भारत के आर्थिक विकास और सुनहरे कल के प्रति जापान में कितना विश्वास और आशावादी वातावरण है और इस निवेश को देख कर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में भारत और जापान के बीच बढ़ते बिज़नेस के साथ लोगों के बीच संबंध भी बढ़ेंगे। ■

भारत की पहली बुलेट रेल परियोजना की रखी गई आधारशिला

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे ने 14 सितम्बर को संयुक्त रूप से मुम्बई और अहमदाबाद के बीच भारत की पहली तेज गति वाली बुलेट रेल परियोजना की आधारशिला रखी। अहमदाबाद में इस मौके पर मौजूद जनसमुदाय को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'न्यू इंडिया' की उच्च महत्वाकांक्षा और इच्छाशक्ति के बारे में बताया। इस मौके पर उन्होंने देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि बुलेट रेलगाड़ी परियोजना तेजी एवं विकास उपलब्ध कराएगी और इसके जल्द नतीजे आएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान तेज सम्पर्क के जरिये उत्पादन बढ़ाने पर है। प्रधानमंत्री ने इस परियोजना के लिए तकनीकी और आर्थिक मदद मुहैया कराने के लिए जापान को धन्यवाद दिया। उन्होंने इस बात के लिए प्रधानमंत्री श्री आबे की सराहना की कि इतने कम समय में इस परियोजना की शुरुआत हो रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि तेज गति वाली इस रेलगाड़ी से न सिर्फ दोनों शहरों की दूरियां घटेंगी, बल्कि सैंकड़ों किलोमीटर दूर रह रहे लोग एक-दूसरे के नजदीक आएंगे। उन्होंने कहा कि मुम्बई-अहमदाबाद गलियारे पर एक नई आर्थिक व्यवस्था विकसित की जा रही है, जिससे पूरा इलाका एकल आर्थिक क्षेत्र के रूप में बदल जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी तभी लाभदायक है, जब वह आम लोगों को फायदा पहुंचाए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में हस्तांतरित प्रौद्योगिकी से भारतीय रेल को लाभ पहुंचेगा और इससे 'मेक इन इंडिया' की पहल को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परियोजना वातावरण के अनुकूल होने के साथ ही मानव के अनुकूल भी होगी। उन्होंने कहा कि "हाई स्पीड गलियारे" भविष्य में तेज गति के साथ विकास के क्षेत्र के रूप में उभरेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि बुनियादी ढांचे का विकास भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाए। उन्होंने यह उम्मीद जताई कि इस परियोजना को कम से कम समय में पूरा करने के लिए सभी लोग मिल कर काम करेंगे। इससे पहले जापान के प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी विशिष्ट, रणनीतिक और वैश्विक है और उन्हें उम्मीद है कि वे कुछ वर्ष बाद भारत का सौन्दर्य बुलेट ट्रेन के जरिए देखेंगे।

मनरेगा कामगारों का 96 प्रतिशत भुगतान सीधे बैंक खातों में जमा

पिछले दो वर्षों में मनरेगा योजना के कार्यान्वयन में प्रमुख बदलाव देखे गए हैं। आईसीटी उपकरणों के उपयोग, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, लोगों की आजीविका के संसाधन आधार को बेहतर बनाने पर फोकस, सम्मिलित कार्यक्रम कार्यान्वयन के माध्यम से रोजगार के विविध अवसरों का प्रावधान इस कार्यक्रम के प्रबंधन में लाए गए परिवर्तनों की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं। इस कानून के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उच्च बजट आवंटन और निगरानी प्रणाली की सुदृढ़ता को सुनिश्चित किया गया है।

मनरेगा कामगारों को समय पर भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए नेशलन इलेक्ट्रॉनिक फंड मेनेजमेंट सिस्टम (एनईएफएमएस) को लागू किया गया है। लगभग 96 प्रतिशत भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कराया जा रहा है। इसके अलावा गहन निगरानी और भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए जवाबदेही तय करने की बदौलत चालू वित्त वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण नतीजे प्राप्त हुए। लगभग 85 प्रतिशत मजदूरी कामगारों को समय पर प्रदान किया जाना संभव हो सका है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में यह प्रतिशत लगभग दो गुणा है।

इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में और अधिक पारदर्शिता तथा जवाबदेही लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फंड मेनेजमेंट सिस्टम (ईएफएसएस), आधार से जोड़े जाने, परिसम्पत्तियों की जियो टैगिंग करने और सामाजिक परीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने जैसे कुछ कदम उठाए गए हैं। कुछ अन्य उपायों में कार्य संबंधी फाइल का उचित अनुरक्षण, जन सूचना प्रणालियों के अंग के रूप में नागरिक सूचना बोर्डों का गठन शामिल हैं।

चालू वित्त वर्ष में आवंटित की गई 48000 करोड़ रूपये की राशि अब तक का सर्वाधिक बजट आवंटन है। ■

सरकार ने कुपोषण से निपटने के लिए अतिरिक्त 12,000 करोड़ रुपये प्रदान किए

अगले तीन वर्षों के दौरान कुपोषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 12,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रदान की है। आंगनवाड़ी और किशोरियों के लिए योजना के तहत पूरक पोषण प्रदान किए जाने वाले लागत मानकों को संशोधित करके उक्त धनराशि जारी की गई है। महिला एवं बाल विकास सचिव श्री राकेश श्रीवास्तव ने 22 सितंबर को कहा कि सरकार ने लागत मानकों में लगभग 33 प्रतिशत का इजाफा कर दिया है। 2011 के बाद पहली बार इन्हें संशोधित किया गया है। किशोरियों के लिए योजना के संबंध में लागत मानकों को 2010 के बाद पहली बार बढ़ाया गया है। इस तरह आंगनवाड़ियों के लिए अगले तीन वर्षों के दौरान पूरक पोषण के संबंध में 9900 करोड़ रुपये अतिरिक्त धनराशि दी गई है। इसके अलावा किशोरियों के लिए योजना में अगले तीन वर्षों के दौरान 2276 करोड़ रुपये का इजाफा किया गया है। दरअसल, यह प्रयास देश में कुपोषण का युद्ध स्तर पर मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप है।

लागत मानकों को खाद्य मूल्य सूचकांक से भी जोड़ दिया गया है, जिसके कारण सरकार को हर वर्ष बिना किसी बाधा के लागत मानकों को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। गौरतलब है कि हाल में कुपोषण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें जिलाधिकारियों से आग्रह किया गया था कि वे अपने-अपने जिलों में कुपोषण को समाप्त करने का दायित्व पूरा करें। उनसे कहा गया था कि वे तीन महीने में एक बार बच्चों और महिलाओं की पोषण/स्वास्थ्य स्थिति का गहराई से आकलन करें तथा हर वर्ष कुपोषण/शारीरिक विकास अवरोध में 2 से 3 प्रतिशत की कमी सुनिश्चित करें। ■

भारतीय जनसंघ की अर्थ नीति

(भारतीय जनसंघ उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक सम्मेलन सीतापुर,1953 के अवसर पर कार्यकर्ता शिविर के लिए दीनदयालजी द्वारा जनसंघ की अर्थ नीति पर लेख)

दीनदयाल उपाध्याय

क्रमशः

भूमि व्यवस्था में परिवर्तन

कृषि-क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने और संपूर्ण जनशक्ति का उपयोग करने के लिए वर्तमान भूमि व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है। भूमि का पुनः वितरण करना होगा। प्रश्न खड़ा होता है कि इस वितरण का आधार क्या हो? काम का अधिकार सिद्धांत के अनुसार इसका सीधा उत्तर यह कि जीतने वाले ज़मीन के अधिकारी बनें। संत विनोबा इसी वितरण के लिए भूदान का महान् यज्ञ कर रहे हैं। वे वृत्ति परिवर्तन की बात कहते हैं, जो भारतीय सिद्धांत के अनुसार सही है। वृत्ति परिवर्तन के साथ इस आशय का क़ानून तो बनाना ही होगा। भूमि के पुनर्वितरण का दूसरा प्रश्न यह है कि जमींदार-नंबरदार आदि नामों से स्थान-स्थान पर रहने वाले बीच वालों का क्या हो। स्पष्ट है कि बिना मुआवजा दिए उनका उन्मूलन होना चाहिए, परंतु उनके पुनर्वास के लिए शासन की ओर से सहायता अवश्य दी जानी चाहिए। तीसरा प्रश्न भूमिहीन श्रमिकों (Landless labour) का है। वस्तुतः ग्रामोद्योगों की उचित व्यवस्था हो जाने पर यह प्रश्न इतना कठिन नहीं रहता, क्योंकि ग्रामवासी तब समग्र रूप से भूमि पर निर्भर नहीं रहते। फिर भी ऐसे श्रमिकों के हित में भूमि पर उनके लिए कुछ पारंपरिक अधिकारों का विकास करना होगा। जैसे भूमि पर से उनका हटाया न जाना। भूमि की बिक्री अथवा हस्तांतरण की स्थिति में भी उन्हें उस पर काम करने दिया जाएगा आदि।

कृषि का उत्पादन

कृषि का उत्पादन बढ़ाने के संबंध में कृषकों को अच्छा बीज, हल,

भारतीय सिद्धांत के अनुसार श्रम यदि अधिकार है, तो कर्तव्य भी है, यह हम कह चुके हैं। कोई दूसरा हमें इस अधिकार से वंचित न करे और न हम स्वयं इससे स्वतः को वंचित होने दें। हड़तालों को घटाने के लिए औद्योगिक न्यायालयों में सुधार करना पड़ेगा। यह व्यवस्था करनी होगी कि वे शीघ्र निर्णय दें और उनके निर्णय पूंजीपतियों द्वारा भी मनवाए जाएं।

आर्थिक सहायता आदि देने की भी व्यवस्था अवश्य करनी होगी। समुचित रूप से कृषि शिक्षा की भी व्यवस्था अनिवार्य है। आज धन प्राप्ति की दृष्टि से बहुत मात्रा में लगाई जाने वाली फ़सलों (Cash crops) के कारण अन्न की फ़सल (Food crops) का उगाया जाना घट गया है और खाद्याभाव का यह भी एक प्रमुख कारण है। अतः दोनों प्रकार की फसलों में संतुलन पैदा करते हुए उत्पादन की योजना की जानी चाहिए।

छोटी और सस्ती मशीनों का उपयोग

खेती में ट्रैक्टर आदि का उपयोग किया जाए अथवा नहीं, यह प्रश्न खड़ा होने पर यही कहना पड़ता है कि वर्तमान स्थिति में इनका उपयोग विशेष कृषि योजनाओं को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं किया जाना चाहिए। अभी तो हल ही पर्याप्त है। उसमें जो सुधार संभव हो, किए जा सकते हैं। छोटे और सस्ते ट्रैक्टर जो सुना है, जापान में बनने लगे हैं, यदि हों तो उनका प्रयोग आरंभ करने का विचार किया जा सकता है।

भूमि कर कितना हो, यह भी महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा निश्चित मत है कि सरकार जमींदार से जितना कर लेती थी, उतना ही कृषक से भी ले। शेष धन का उपयोग विविध रूप से ग्राम सुधार में ही किया जाना चाहिए। ग्राम सुधार और कृषक उन्नति के लिए सहकारी संस्थाओं का बड़ा महत्व है और उनके विकास पर पूर्ण ध्यान दिया जाना चाहिए।

कुटीर उद्योग

औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने, जनता को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाने तथा संपत्ति के सम विभाजन की व्यवस्था करने के लिए हमें कुटीर-उद्योगों को पुनः विकसित करना पड़ेगा। प्राचीन भारत

का संपूर्ण आर्थिक ढांचा इन कुटीर उद्योगों पर ही खड़ा था। उस समय न केवल देश स्वावलंबी था, वरन् लघुतम इकाई ग्राम तक स्वावलंबी थे और संपत्ति के संचय का प्रश्न भी नहीं था। इसके अलावा उत्पादित सामग्री के कलात्मक मूल्य भी बहुत अधिक थे। अंग्रेजों ने भारतीय समाज जीवन की इसी रीढ़ को तोड़ने की सफल चेष्टा की और इसी के बाद वे अपने यहां उत्पादित अधिक सामग्री को यहां खपा सके। आर्थिक स्वाधीनता के लिए हमें इसी रीढ़ को पुनः खड़ा करना होगा। इस काल में विश्व जो वैज्ञानिक उन्नति कर चुका है, उसको ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था का बाहरी रूप कुछ बदलना होगा। जापान इस दिशा में भारत की बहुत कुछ सहायता कर सकता है। कुटीर-उद्योगों में ही हम संपूर्ण जनशक्ति का उपयोग कर सकते हैं, जो हमारी एक प्राथमिक ज़िम्मेदारी है।

वितरण व्यवस्था

उत्पादन के बाद अब वितरण का सवाल आता है। उत्पादन की जो उपर्युक्त व्यवस्था हमने देखी उसमें वितरण को असमान न होने देने की क्षमता है। समानता के लिए पूंजी का केंद्रीकरण न हो, इस बात

संस्कृति न केवल इसकी ओर ध्यान देती है, वह इस पर बल भी देती है। वह कहती है कि अनियंत्रित उपभोग असमान वितरण का कारण है। उपभोग में संयम बरतने वाला और सादा व्यक्ति अपनी चेष्टा से अपने परिवार का ही नहीं, संपूर्ण समाज और मानव मात्र का जीवन बदल दे सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार उत्पादन उपभोग का नियंत्रण नहीं करता, उपभोग ही उत्पादन का नियंत्रण करता है।

का ध्यान रखना आवश्यक है। इसीलिए विकेंद्रित उद्योग-धंधों की व्यवस्था है। जहां तक कुटीर उद्योगों का सवाल है, यह खतरा बहुत कम है, लेकिन जहां बड़े उद्योगों का क्षेत्र शुरू होता है, वहां यह खतरा उत्पन्न होता है। सुरक्षा उद्योगों का तो राष्ट्रीयकरण अनिवार्य है। अब प्रश्न बनता है पूंजी उद्योगों का। उनका भी अंतिम रूप से राष्ट्रीयकरण कर देना उद्देश्य होना चाहिए। आज पूंजी उद्योग व्यक्तिगत क्षेत्र में आते हैं। उनसे व्यक्तिगत क्षेत्र का क्रमिक उन्मूलन किया जाना चाहिए। जब तक यह राष्ट्रीयकरण अंतिम रूप से संपन्न नहीं हो जाता, तब तक बड़े उद्योगों के गुट (Cartela and combines) बनने देने की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। जिन उद्योगों में ये गुट बन गए हों, उनका राष्ट्रीयकरण कर लिया जाए। कुटीर उद्योगों का विकास करते समय भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनके गुट बनाकर पूंजीपति उन पर नियंत्रण न स्थापित कर लें। जापान में वितरण तथा संपत्ति की असमानता का कारण वहां के कुटीर उद्योगों पर पूंजीपतियों का नियंत्रण ही है।

श्रम और पूंजी का संबंध

बड़े उद्योगों के साथ ही श्रम और पूंजी के संबंध का प्रश्न भी खड़ा होता है। उद्योगों पर दोनों का समान दायित्व और समान अधिकार मानना मूल बात है। इसका परिणाम होता है-अधिक काम और अधिक काम। मजदूरों की मांगों को मनवाने का अस्त्र हड़ताल है, लेकिन उसका उपयोग बहुत सोच-समझकर और अंतिम रूप में ही किया जाना चाहिए। भारतीय सिद्धांत के अनुसार श्रम यदि अधिकार है, तो कर्तव्य भी है, यह हम कह चुके हैं। कोई दूसरा हमें इस अधिकार से वंचित न करे और न हम स्वयं इससे स्वतः को वंचित होने दें। हड़तालों को घटाने के लिए औद्योगिक न्यायालयों में सुधार करना पड़ेगा। यह व्यवस्था करनी होगी कि वे शीघ्र निर्णय दें और उनके निर्णय पूंजीपतियों द्वारा भी मनवाए जाएं।

संयमित उपभोग

तीसरा और अंतिम प्रश्न है उपभोग का। पश्चिमी देशों की आर्थिक क्रांति और विचार प्रक्रिया के संपूर्ण इतिहास में अर्थव्यवस्था के इस तीसरे पक्ष की ओर प्रायः बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। भारतीय संस्कृति न केवल इसकी ओर ध्यान देती है, वह इस पर बल भी देती है। वह कहती है कि अनियंत्रित उपभोग असमान वितरण का कारण है। उपभोग में संयम बरतने वाला और सादा व्यक्ति अपनी चेष्टा से अपने परिवार का ही नहीं, संपूर्ण समाज और मानव मात्र का जीवन बदल दे सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार उत्पादन उपभोग का नियंत्रण नहीं करता, उपभोग ही उत्पादन का नियंत्रण करता है। अमर्यादित और असंयत उपभोग की वह वृत्ति है, जो स्वदेश के उत्पादन से तृप्त न होकर विदेशों पर नजर डालती है और उन्हें खा डालने की इच्छा से साम्राज्यवाद के भयंकर रूप में प्रगट होती है।

मोटे तौर पर यह भारतीय विकेंद्रित अर्थ नीति की रूपरेखा है। इसमें संपत्ति सिद्धांतः समाज की है, मनुष्य को काम करने का अधिकार है और सभी व्यक्तियों को काम दिलाने की जिम्मेदारी भी है। विश्व की नई आर्थिक क्रांतियों में इस प्रकार के प्रयोग नहीं हुए हैं।

आमदनी के अनुपात के निर्णय का प्रश्न यद्यपि पीछे से नाक पकड़ना है, परंतु यदि उसे भी लें तो भारतीय जनसंघ आमदनियों का अनुपात 1 और 20 करने का निर्णय कर चुका है। यदि कम-से-कम आमदनी 100 रुपए हो तो अधिक-से-अधिक 2000 होनी चाहिए। कर्मचारियों, किसानों, मजदूरों तथा पूंजीपतियों सभी की आमदनी को इस अनुपात में लाने की चेष्टा की जानी चाहिए। ■ (समाप्त)

- पांचजन्य, जनवरी 15, 1954

नहीं रहे 'मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स' अर्जन सिंह

भारतीय वायु सेना के मार्शल श्री अर्जन सिंह का 16 सितम्बर को 98 वर्ष की उम्र निधन हो गया। श्री अर्जन सिंह को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, तीनों सेवाओं के प्रमुख, शहरी विकास राज्यमंत्री व अन्य गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की।

श्री अर्जन सिंह का जन्म 15 अप्रैल, 1919 को अविभाजित भारत के लयालपुर, पंजाब में हुआ था। लयालपुर इस वक्त पाकिस्तान के फैसलाबाद में है। उनका परिवार सैन्य सेवा में था। 1964 में वह वायु सेना के प्रमुख बने। उस समय उनकी उम्र थी महज़ 44 साल। उन्होंने 1965 में पाकिस्तान के साथ जंग के दौरान वायु सेना की कमान संभाली। श्री अर्जन सिंह ने भारतीय वायु सेना में क्षमता निर्माण पर दृढ़ता से ध्यान केंद्रित किया और रक्षा क्षमताओं को मजबूती प्रदान की। भारत 1965 में भारतीय वायु सेना के मार्शल अर्जन सिंह के उत्कृष्ट नेतृत्व को कभी नहीं भूल सकता, जब भारतीय वायु सेना ने पर्याप्त कार्रवाई की।

1971 में रिटायर होने के बाद कई बरसों तक वे बहुत सक्रिय रहे। स्विटज़रलैंड में वे भारत के राजदूत रहे और केन्या में उच्चायुक्त। 1989 से 1990 के बीच वे दिल्ली के उप राज्यपाल भी रहे। श्री अर्जन सिंह को उनके असाधारण योगदान के लिए 2002 में एयर फोर्स का मार्शल बनाया गया। गौरतलब है कि वायु सेना के किसी भी अधिकारी को पहली बार फील्ड मार्शल के बराबर 5 सितारा रैंक दी गई।

मार्शल श्री अर्जन सिंह के निधन पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि 'मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स' अर्जन सिंह जी ने भारतीय वायु सेना का अनुकरणीय नेतृत्व किया। मातृभूमि के लिए उनकी महान सेवा आदरणीय है। ■

प्रधानमंत्री ने किया शोक व्यक्त

अपने ट्विटर एकाउंट से ट्वीट्स की एक शृंखला में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय वायु सेना के मार्शल श्री अर्जन सिंह ने भारतीय वायु सेना में क्षमता निर्माण पर दृढ़ता से ध्यान केंद्रित किया और उन्होंने हमारी रक्षा क्षमताओं को मजबूती प्रदान की। उन्हें एक प्रतिष्ठित वायु योद्धा और एक अच्छा इंसान बताते हुए प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर उनके परिवार और चाहने वालों के प्रति अपना शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा, "भारतीय वायु सेना के मार्शल अर्जन सिंह के निधन से देश दुःखी है। हम देश के लिए उनकी उत्कृष्ट सेवा को याद करते हैं।

कुछ समय पहले मैंने उनसे मुलाकात की, तब अस्वस्थ होने के बावजूद खड़े होकर मुझे सैलूट करने की कोशिश की, हालांकि मैंने मना किया। इस प्रकार का उनमें सैनिक का अनुशासन था। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और उनके चाहने वालों के साथ है, जो एक प्रतिष्ठित वायु योद्धा और अच्छे व्यक्ति, भारतीय वायु सेना के मार्शल अर्जन सिंह की मृत्यु पर दुःखी हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें।"

ब्रह्मलीन हुए महंत चांदनाथ

अलवर से भाजपा सांसद महंत चांद नाथ का 17 सितम्बर को निधन हो गया। श्री चांद नाथ 61 साल के थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा सांसद महंत चांद नाथ के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा, "अलवर के सांसद महंत चांद नाथ जी के निधन से दुःख हुआ, उन्हें उनके समृद्ध सामाजिक कार्यों के लिए याद किया जाएगा। मैं गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं।" राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने श्री चांद नाथ के शोकाकुल परिजन के प्रति संवेदनाएं जाहिर की।

महंत चांदनाथ का जन्म 21 जून, 1956 को दिल्ली के बेगमपुर में हुआ था। उन्होंने दिल्ली के हिन्दू कॉलेज से बीए ऑनर्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। वह 18 साल की उम्र में साधु बन गए थे। महंत चांदनाथ ने 2014 में राजस्थान की अलवर सीट से लोकसभा चुनाव जीता था। श्री चांद नाथ रोहतक स्थित बाबा मस्त नाथ यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे। महंत चांद नाथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थाई समिति और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की परामर्शदाता समिति के सदस्य थे। वह 2004 से 2008 तक राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रहे। ■

प्रधानसेवक नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मनाने का सबसे श्रेष्ठ तरीका

इसे सेवा दिवस के तौर पर मनाना है: अमित शाह

नरेंद्र भाई के जन्मदिन को मनाने का सबसे श्रेष्ठ तरीका इसे सेवा दिवस के तौर पर मनाना ही है। नरेंद्र भाई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका हृदय सदैव गरीबों, समाज के वंचित वर्ग और किसानों के लिए धड़कता रहा है। उनके कल्याण की दिल की गहराई से चिंता करने के भाव ने ही उन्हें अपने युवा काल से राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रेरित किया। अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को उन्होंने इंडिया फर्स्ट के भाव के साथ जिया है।

आज हम अपने प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं और देश सेवा के लिए उनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं।

मैं जब से नरेंद्र भाई को जानता हूं, उन्होंने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। उनके लिए यह दिन रोज के किसी भी दिन के समान होता है। आज भी वो गुजरात में हैं और सरदार सरोवर बांध राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। यह परियोजना लाखों किसानों को लाभ पहुंचाएगी। साथ ही वो स्टेचू ऑफ यूनिटी परियोजना की समीक्षा करेंगे, दाभोई में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे और अमरेली में सहकारी क्षेत्र के लोगों के साथ मुलाकात करेंगे।

मुझे प्रसन्नता है कि आज के दिन को विभिन्न क्षेत्रों के लोग सेवा दिवस के तौर पर मना रहे हैं। कई संगठन और स्वयंसेवी संस्थाएं, विशेषतौर पर युवाओं द्वारा संचालित संगठन आज के दिन सामाजिक सेवाओं के प्रयासों का शुभारंभ कर रहे हैं।

नरेंद्र भाई के जन्मदिन को मनाने का सबसे श्रेष्ठ तरीका इसे सेवा दिवस के तौर पर मनाना ही है। नरेंद्र भाई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका हृदय सदैव गरीबों, समाज के वंचित वर्ग और किसानों के लिए धड़कता रहा है। उनके कल्याण की दिल की गहराई से चिंता करने के भाव ने ही उन्हें अपने युवा काल से राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रेरित किया। अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को उन्होंने इंडिया फर्स्ट के भाव के साथ जिया है।

नरेंद्र भाई में देश की जनता एक प्रेम और करुणा से भरा नेता देखती है, जिसके साथ वो खुद को जोड़ती है। वे उनमें स्वयं का प्रतिबिंब देखते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो चौबीसों घंटे बिना किसी निजी स्वार्थ के राष्ट्र के कल्याण के काम में लगा है। उनकी लोकप्रियता सभी सीमाएं लांघ गई है।

नरेंद्र भाई का जीवन भारत को ही परिलक्षित करता है। जब नरेंद्र भाई कहते हैं कि वो गरीब के लिए ही जिएंगे और मरेंगे, तब ये उनके केवल शब्द ही नहीं है। उन्होंने गरीबी को बेहद नजदीक से देखा है और वह समझते हैं कि गरीब होने के मायने क्या हैं और वह कैसे जीता है। उन्होंने गरीब के जीवन के इस संघर्ष का अनुभव किया है। वह अपनी मेहनत और कड़े परिश्रम के बल पर लोगों के आशीर्वाद के साथ आज

इस स्थान तक पहुंचे हैं। उनकी जीवन यात्रा इस देश के युवाओं को प्रेरणा और आत्मविश्वास से भर देती है कि हां मेरे लिये भी इस नए भारत में अनंत संभावनायें और अवसर हैं।

यह नरेंद्र भाई की गरीबों की इच्छाओं के प्रति संवेदनशीलता ही है, जिसने उन्हें गरीबों के कल्याण के ऐतिहासिक प्रयासों के लिए प्रेरित किया। जन धन योजना की ऐतिहासिक सफलता ने लाखों लोगों के लिए बैंकिंग सिस्टम को खोला है। अब तक ये लोग देश के वित्तीय तंत्र से अलग थलग थे। आगे चलते हुए सरकार ने गरीबों के लिए अब तक के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा अभियान की शुरुआत की।

देश के युवाओं की रचनात्मकता, सृजनशीलता और कुछ कर दिखाने के जज्बे पर नरेन्द्र भाई का अटूट विश्वास है। मुद्रा योजना उनके इसी दृढ़ विश्वास का परिणाम है। यह हर्ष की बात है कि मुद्रा के लाभार्थियों में अधिकांश गरीब परिवारों, छोटे शहरों और ग्रामीण भारत के लोग हैं। देश के युवाओं को उनका संदेश स्पष्ट है-अगर आप अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हो, तो सरकार आपको उड़ने के लिए पंख प्रदान करेगी।

एक भ्रष्ट तंत्र गरीबों को कष्ट देता है। खासतौर पर मध्य वर्ग और उभरते हुए मध्य वर्ग के लिए यह बेहद कष्टकारी साबित होता है। यह लोगों में सिस्टम के प्रति भरोसा भी कम करता है। नरेंद्र भाई ने प्रधानमंत्री के तौर पर कामकाज संभालने के बाद सबसे पहला काम

यही किया कि कालेधन पर एक विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया। तब से अब तक कालेधन के खिलाफ कई मामलों में कार्यवाही की जा चुकी है और भ्रष्टाचार रोकने के लिए नोटबंदी और बेनामी संपत्ति कानून लाने जैसे कदम उठाए गए। ईमानदार करदाता, जिनमें से अधिकांश मध्यम वर्ग से आते हैं आज संतुष्ट और गर्व महसूस करते हैं।

नरेंद्र भाई ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और वर्षों से चली आ रही कुछ चुनिंदा लोगों को सुविधा मिलने की परंपरा समाप्त हुई है। गरीबों को अब उनका अधिकार मिल रहा है। नरेंद्र भाई से अक्सर लोग पूछते हैं कि आपको ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने की ताकत कहां से मिलती है। तब वह अपने ही अंदाज में कहते हैं – मैं यहां गरीब के लिए काम कर रहा हूं। मैं किसी से क्यों डरूं। यह राष्ट्र ही मेरा परिवार है। मैं यहां अपनी किसी विरासत को मजबूत करने के लिए नहीं हूं, मैं केवल और केवल भारत के लिए काम करूंगा।

किसी काम को करने की प्रतिबद्धता नरेंद्र भाई की सबसे बड़ी खूबी है। अगर कोई चीज देश के लिए अच्छी है तो वह उसे पूरी दृढ़ता और विश्वास के साथ आगे ले जाते हैं। उनकी यह प्रतिबद्धता और निश्चितता भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में देखी जा सकती है। सरकार ने आंतकवाद के वित्त पोषण और आतंकवादियों के विरुद्ध कड़े कदम उठाए हैं। आतंकवादियों के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत कितना सक्षम है। कूटनीतिक तौर पर भी आज नरेंद्र भाई आतंकवाद के खिलाफ दुनिया के देशों का समर्थन भारत के पक्ष में लाने में सफल रहे हैं।

भारत सरदार पटेल को देश को एक सूत्र में बांधने के लिए सदैव याद करेगा। साथ ही डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर को समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इसी तरह जनधन से लेकर जीएसटी तक नरेंद्र भाई ने देश को आर्थिक एकता के सूत्र में पिरोने के काम की शुरुआत की है।

किसी भी कार्य को आगे ले जाने का दिशा बोध, उसको करने की अदम्य इच्छाशक्ति और उसकी हर बारीकी की गहराई में जाने का स्वभाव उनको एक आदर्श संगठक बनाता है। दूरदराज के क्षेत्रों में संगठन का कार्य, पार्टी के प्रवक्ता या महासचिव पद तक ऐसा कोई काम नहीं है, जहां नरेंद्र भाई ने अपनी संगठन कौशल की छाप नहीं छोड़ी हो। अपने विस्तृत सांगठनिक कामकाज के चलते वह देश के प्रत्येक जिले में रहे और देश की समृद्ध विविधता का प्रत्यक्ष अनुभव किया।

गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का कार्य करते थे तब और दिल्ली में महासचिव के अपने कार्यकाल के दौरान और आज भी नरेंद्र भाई युवा कार्यकर्ताओं के लिये एक प्रेरणास्त्रोत रहे हैं। उन्होंने हमेशा युवा, ख़ुद के बल पर और जमीन से उठकर आने वाले कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम किया और उन युवाओं में काम करने की भावना को पोषित किया, न कि सत्ता में आने की भावना को। उन्होंने युवाओं को हमेशा कहा कि कुछ बनने की चाह नहीं, बल्कि कुछ करने की चाह पैदा करो।

नरेंद्र भाई से मेरी पहली मुलाकात एक युवा बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में हुई। उस वक्त भाजपा देश में उभरने का प्रयास कर रही थी। हममें से कोई भी सत्ता की तरफ नहीं देख रहा था। सत्ता हमारे लिए कोई विषय ही नहीं था। हमारा तो प्रत्येक क्षण केवल भारत के कल्याण के प्रति समर्पित था। बाद में 1995 और 1998 के गुजरात चुनाव के दौरान और पार्टी के अन्य मंचों पर मुझे नरेंद्र भाई के नजदीक रहकर काम करने का मौका मिला। यही नहीं, मुझे सात साल तक नरेंद्र भाई के नेतृत्व में गुजरात के गृह मंत्री के तौर पर काम करने का मौका भी मिला। यही वक्त था जब मैंने उनकी प्रशासन पर पकड़ का प्रत्यक्ष अनुभव किया। उन्होंने कैसे पूरे गुजरात को एक आदर्श राज्य के तौर पर सुशासन के साथ विकसित किया, इसका भी मैं गवाह रहा हूं।

एक बार फिर मैं अपने समस्त देशवासियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवार के साथ नरेंद्र भाई को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम देश की सेवा में इसी तरह काम करते रहें और उन्हें भारत को सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अपना समर्थन और सहयोग देते रहेंगे। आइए इस दिन को और आने वाले दिनों को नरेंद्र भाई के एक विशेष मिशन स्वच्छ भारत मिशन के लिए समर्पित करें। 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान में अपना सक्रिय योगदान दें, ताकि महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा किया जा सके।

मेरा आप सभी से अनुरोध है कि स्वच्छता के प्रयासों में सक्रियता और उत्साह से शामिल हों और अपने प्रयास की फोटो नरेंद्र मोदी मोबाइल एप पर साझा करें, ताकि दूसरे लोग भी आपके कामों को देखकर प्रेरणा ले।

वंदे मातरम! ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं)

गत 17 सितंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 67वें जन्मदिन को भाजपा द्वारा देश भर में 'सेवा दिवस' के रूप में मनाया गया और इस अवसर पर चिकित्सा एवं रक्तदान शिविर और स्वच्छता अभियान जैसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा, "भारत को पुनः विश्व गुरु के स्थान पर आसीन करने के लिए निरंतर प्रयासरत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस पर उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रसेवा के लिए ईश्वर से आपके उत्तम स्वस्थ एवं दीर्घायु की कामना करता हूं।"

स्वच्छता में निवेश का अर्थशास्त्र

स्वच्छता के महत्व को दस्तावेजी रूप पहले ही दिया जा चुका है। इसके प्रभाव से डायरिया जैसी बीमारियों में आने वाली कमी बाल मृत्यु दर को नीचे लाती है। इससे स्त्रियों की सुरक्षा और उनकी गरिमा सुनिश्चित होती है। स्वच्छता की कमी से होने वाला नुकसान उससे कहीं ज्यादा है, जितना यह ऊपर से नजर आता है।

अरुण जेटली

कहते हैं, जिस विचार का समय आ गया हो उसे कोई रोक नहीं सकता। एक रक्तरंजित विश्वयुद्ध की पृष्ठभूमि में जब हिंसा ही युग की पहचान हुआ करती थी, भारत ने अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन के जरिये, सत्याग्रह के जरिये स्वतंत्रता हासिल की। पूरा देश महात्मा के आह्वान के पीछे आ गया और अपनी स्वतंत्रता के रूप में भारत ने संसार के सामने एक मिसाल पेश कर दी। यह एक ऐसा विचार था जिसका समय आ चुका था। उसी तरह आज, जब भारत का नाम खुले में शौच करने वालों की सबसे बड़ी तादाद के साथ इसके लिए बदनाम देशों की सूची में सबसे ऊपर है, 2 अक्टूबर 2019 तक पूर्ण स्वच्छता प्राप्ति के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री द्वारा किया गया स्वच्छ भारत का आह्वान एक ऐसा विचार है जिसका समय आ गया है।

खुले में शौच जाने की परंपरा मानव सभ्यता के प्रारंभ जितनी ही पुरानी है। भारत के करोड़ों लोगों के लिए यह सदियों से जीवन शैली का हिस्सा है। 1980 के दशक से ही हमारे यहां सारी सरकारें राष्ट्रीय स्वच्छता कार्यक्रम संचालित करती आ रही हैं, लेकिन 2014 तक केवल 39 प्रतिशत भारतीयों को ही शौच की सुरक्षित सुविधा उपलब्ध थी। कारण यह कि शौचालय तक लोगों की पहुंच होना कोई ढांचागत समस्या नहीं है। इस मामले में लोगों का व्यवहारगत रवैया और सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ कहीं ज्यादा बड़ी भूमिका निभाता है। 60 करोड़ों लोगों के व्यवहार को प्रभावित करना एक ऐसी चुनौती है, जिसका सामना करने की अभी तक संसार में किसी ने कोशिश भी नहीं की है। यह उपलब्धि केवल एक सघन, समयबद्ध हस्तक्षेप के जरिये ही हासिल की जा सकती है, जिसका नेतृत्व सर्वोच्च स्तर से किया जा रहा हो और जिसमें समाज व सरकार के सभी अंग मिल-जुल कर सक्रिय हों। स्वच्छ भारत मिशन के स्वच्छाग्रह ने राष्ट्र की कल्पना को ठीक उसी तरह आकृष्ट किया है, जिस तरह दशकों पहले महात्मा के सत्याग्रह ने किया होगा।

स्वच्छता के महत्व को दस्तावेजी रूप पहले ही दिया जा चुका है। इसके प्रभाव से डायरिया जैसी बीमारियों में आने वाली कमी

बाल मृत्यु दर को नीचे लाती है। इससे स्त्रियों की सुरक्षा और उनकी गरिमा सुनिश्चित होती है। स्वच्छता की कमी से होने वाला नुकसान उससे कहीं ज्यादा है, जितना यह ऊपर से नजर आता है। विश्व बैंक का एक अध्ययन बताता है कि मुख्यतः स्वच्छता की कमी के चलते भारत के 40 फीसदी बच्चों का शारीरिक और बौद्धिक विकास नहीं हो पाता। हमारी भावी कार्यशक्ति का इतना बड़ा हिस्सा अपनी पूर्ण उत्पादक क्षमता ही हासिल न कर सके, यह हमारी मुख्य शक्ति, हमारे जनसंख्या बल के लिए एक गंभीर खतरा है। इस समस्या को सुलझाना आर्थिक महाशक्ति बनने से जुड़ी हमारी विकास कार्यसूची का आधार बिंदु होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक का भी अनुमान है कि स्वच्छता के अभाव से भारत को उसकी जीडीपी के 6 फीसदी का नुकसान होता है।

यूनिसेफ के एक अध्ययन के मुताबिक खुले में शौच से मुक्त गांवों में हरेक परिवार ने साल में 50,000 रुपये बचाए। यह बचत दवाओं पर होने वाले खर्च में आई कमी तथा समय व जीवन बचने से हासिल हुई। इसके अलावा समुचित ठोस व द्रव कचरा प्रबंधन से अच्छी मात्रा में धन प्राप्ति की भी संभावना है। इसमें यह भी बताया गया है कि स्वच्छता से होने वाला प्रति परिवार आर्थिक लाभ 10 वर्षों के समेकित निवेश (सरकारी व अन्य स्रोतों द्वारा किए गए खर्च तथा परिवार द्वारा लगाए गए पैसे) का 4.7 गुना है। जाहिर है, स्वच्छता उम्मीद से ज्यादा फायदा देने वाला निवेश है। स्वच्छ भारत मिशन पर केंद्र व राज्य सरकारें पांच वर्षों में 20 अरब डॉलर खर्च करने वाली हैं। इसके अलावा निजी क्षेत्र, विकास एजेंसियों, धार्मिक संगठनों और नागरिकों की ओर से भी इसके लिए राशि आ रही है।

स्वच्छ भारत कोष द्वारा विशेष सफाई परियोजनाओं के लिए 660 करोड़ रुपये की राशि इकट्ठा की गई और उसे जारी भी कर दिया गया। यह राशि लोगों के व्यक्तिगत योगदान और कंपनियों व संस्थानों की मदद से जुटाई गई। इसमें सबसे ज्यादा 100 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत योगदान धार्मिक नेता माता अमृतानंदमयी का रहा। कई निजी कंपनियों ने अपने सीएसआर फंड से स्कूलों में सफाई की व्यवस्था की है, हालांकि स्वच्छ भारत मिशन में अब भी निजी क्षेत्र की रचनात्मकता और नवाचार के लिए पर्याप्त संभावनाएं मौजूद हैं। भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग अपने-अपने क्षेत्रों में स्वच्छता को प्रमुखता देने के लिए प्रयास कर रहे हैं और वे इस पर एक निश्चित राशि खर्च करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। वित्त वर्ष 2017-18 में यह राशि 12,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की होगी।

स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में कहें तो तेजी से एक जनांदोलन का रूप लेता जा रहा है। खुले में शौच करने वालों की संख्या काफी कम हो गई है। देश की 68 फीसदी से ज्यादा आबादी के पास अब सुरक्षित शौच की सुविधा उपलब्ध है। खुले में शौच करने वाले अब 30 करोड़ से कुछ ही ज्यादा बचे हैं। मगर अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। इस मुहिम को और तेज करने के लिए सरकार 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच 'स्वच्छता ही सेवा' पखवाड़ा मना रही है। इस दौरान मंत्रियों, सांसदों, केंद्र तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों से लेकर बड़ी-बड़ी हस्तियों, संगठनों, उद्योगपतियों, स्थानीय नेताओं और आम नागरिकों तक हर कोई श्रमदान के जरिए खुद को स्वच्छता के प्रति समर्पित करेगा। इस प्रकार सब मिलकर स्वच्छ भारत मिशन की संक्रामक ऊर्जा को और फैलाते जाएंगे तो फिर सबके लिए एक मौका है। अपनी-अपनी आस्तीनें चढ़ाइए और गांधी जी के सपनों का भारत, स्वच्छ भारत बनाने के अभियान में जुट जाइए। आप ये पंक्तियां पढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ें और अपने हिस्से का कर्तव्य पूरा करें। ■

(लेखक केंद्रीय वित मंत्री हैं)

(नवभारत टाइम्स से साभार)

सप्ताह में चलाएंगे एक दिन साइकिल

सप्ताह में एक दिन डीजल पेट्रोल चलित निजी वाहन को न चलाने का अगर संकल्प लें तो यह भी देश सेवा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के "मन की बात" कार्यक्रम में इस उद्‌गार से प्रेरित होकर ग्वालियर (मप्र) में साइकिल रैली निकाली गयी। रैली प्रारम्भ होने के पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने उपस्थित लगभग 20 हजार साइकिल सवारों को शपथ दिलाई कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने, ईंधन के रूप में डीजल पैटोल बचाने एवं सप्ताह में एक दिन साइकिल चलाएंगे और 2017 का संकल्प 2022 में सिद्ध होगा जिससे नये भारत का निर्माण होगा। इस रैली में राज्य शासन के मंत्री द्वय श्री जयभान सिंह पवैया एवं श्रीमती माया सिंह सहित अनेक विशिष्ट जन उपस्थित थे। इस रैली के संयोजक प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री राजेश सोलंकी थे। ■

'राज्य में विकास की बयार के लिए परिवर्तन लाना है'

युवाओं के जोश और उत्साह से यह साफ़ है कि इस बार के विधान सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 50 से अधिक सीटें जीतकर हिमाचल प्रदेश में तीन-चौथाई बहुमत से सरकार बनायेगी। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि आजादी के बाद से इतनी बदनामी हिमाचल प्रदेश की कभी नहीं हुई, जितनी कांग्रेस की वीरभद्र सिंह सरकार के दौरान इन पांच साल में हुई है।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 22 सितंबर को नगरपालिका ग्राउंड, कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) में युवा हुंकार रैली को संबोधित किया और युवाओं से राज्य के विकास के लिए हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दो-तिहाई बहुमत की सरकार बनाने का आह्वान किया। उन्होंने हिमाचल की मौजूदा कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताते हुए राज्य के विकास के प्रति उसकी उदासीनता व अकर्मण्यता को लेकर वीरभद्र सरकार पर करारा प्रहार किया।

श्री शाह ने कहा कि युवाओं के जोश और उत्साह से यह साफ़ है कि इस बार के विधान सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 50 से अधिक सीटें जीतकर हिमाचल प्रदेश में तीन-चौथाई बहुमत से सरकार बनायेगी। उन्होंने कहा कि मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि आजादी के बाद से इतनी बदनामी हिमाचल प्रदेश की कभी नहीं हुई, जितनी कांग्रेस की वीरभद्र सिंह सरकार के दौरान इन पांच साल में हुई है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 'हिसाब मांगे हिमाचल' अभियान से जुड़ने के लिए एक नंबर जारी किया है, आप 7574068068 पर मिस्ड कॉल देकर हिमाचल प्रदेश के परिवर्तन के अभियान से जुड़ सकते हैं।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को हटाकर भाजपा की सरकार लाने के लिए हमें परिवर्तन नहीं लाना है। किसी को मंत्री अथवा मुख्यमंत्री बनाने के लिए परिवर्तन नहीं करना है, बल्कि प्रदेश की व्यवस्था को बदलने के लिए, राज्य में विकास की बयार लाने के लिए परिवर्तन करना है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए डबल इंजन वाले ग्रोथ की जरूरत है। आपने केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर एक इंजन तो लगा दिया है, अब हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनाकर दूसरा इंजन भी लगा दें, प्रदेश का विकास डबल इंजन की स्पीड से आगे बढ़ेगा।

श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार, बलात्कार, गुंडागर्दी और माफियागिरी ने देवभूमि हिमाचल प्रदेश को बर्बाद कर के रख दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद से देश के सभी राज्यों के राजस्व में इजाफा हुआ, लेकिन हिमाचल की

कांग्रेस सरकार पूरे भारत में एकमात्र ऐसी सरकार है जिसके राजस्व में कमी आई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के राजस्व में लगभग 4,200 करोड़ रुपये की कमी आई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं पर राज्य की वीरभद्र सरकार ने लगभग 46,000 करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ डालने का काम किया है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इतने सारे हाइवे के प्रोजेक्ट्स हिमाचल को दिए हैं, लेकिन वीरभद्र सरकार हाइवेज का सर्वे कराने में भी असमर्थ रही। उसके लिए भी केंद्र की भाजपा सरकार ने 268 करोड़ रुपये की राशि अलग से आवंटित की है। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सरकार हिमाचल प्रदेश का विकास नहीं कर सकती, यदि हिमाचल प्रदेश का विकास करना है तो राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हिमाचल के विकास के लिए कई काम किये हैं चाहे सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स हों, हाइड्रो पॉवर के प्रोजेक्ट्स हों या फिर 3900 किलोमीटर का हाइवे प्रोजेक्ट्स। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों की भी हरसंभव सहायता करने का काम मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार केन्द्रीय योजनाओं में हिमाचल प्रदेश को 90% आर्थिक सहायता दे रही है, इसके बावजूद हिमाचल में विकास की रफ़्तार सुस्त है। ■

'आपको रोजगार के लिए पहाड़ छोड़ना पड़े, ऐसी स्थिति नहीं आने दी जाएगी'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 19 सितंबर को ओएनजीसी ऑडिटोरियम, देहरादून उत्तराखंड) में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, सिद्धांतों और कार्यपद्धति पर विस्तार से चर्चा की। विदित हो कि श्री शाह देश के सभी राज्यों में कुल 110 दिनों के अपने विस्तृत प्रवास कार्यक्रम के तहत दो दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में थे। इससे पहले देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन किया गया। तत्पश्चात् श्री शाह ने देहरादून में प्रदेश पदाधिकारी, सांसद, विधायक, मेयर, जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री व अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक कर संवाद किया। इसके पश्चात् उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय कार्य विस्तार योजना की समीक्षा बैठक भी की। श्री शाह ने कहा कि यह वर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म शताब्दी वर्ष है।

उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी न केवल भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष रहे बल्कि उन्होंने जन संघ के माध्यम से एक ऐसी पार्टी की नींव रखी, जो सिर्फ राजनीतिक कारणों से राजनीति में नहीं है, बल्कि देश में परिवर्तन की बयार लाने के लिए है। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने जीवनपर्यंत कार्य किया और उसी का परिणाम है कि जन संघ के रूप में 11 सदस्यों से शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी आज 11 करोड़ से अधिक सदस्यों के साथ विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हमारा वादा है पहाड़ के युवाओं से - आपको रोजगार के लिए पहाड़ छोड़ना पड़े, ऐसी स्थिति नहीं आने दी जायेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इतने सालों तक उत्तराखंड में जो गंदगी फैला रखी थी, अभी उसकी स्वच्छता में राज्य की त्रिवेन्द्र सिंह रावत सरकार लगी हुई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार राज्य के विकास के लिए अहर्निश काम कर रही है और देखते ही देखते उत्तराखंड भी भाजपा सरकार के नेतृत्व देश के एक विकसित प्रदेश के रूप में प्रतिस्थापित होगा। ■

'रावत सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए कटिबद्ध'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 20 सितंबर को होटल मधुबन, देहरादून (उत्तराखंड) में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने उत्तराखंड के विकास के लिए कई कदम उठाये हैं। उन्होंने कहा कि 13वें वित्त आयोग में कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार ने शेयर इन सेन्ट्रल टैक्स के रूप में उत्तराखंड को 15,965 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की थी, जबकि 14वें वित्त आयोग में मोदी सरकार ने उत्तराखंड के लिए पांच वर्षों में 41,665 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है जो 13वें वित्त आयोग के मुकाबले लगभग तीन गुनी अधिक है। उन्होंने कहा कि ग्रांट इन ऐड के तौर पर 13वें वित्त आयोग में कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार ने उत्तराखंड को 3,295 करोड़ रुपये दिए थे, जबकि मोदी सरकार ने इसे बढ़ा कर 3,741 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर इन सेक्टरों में 14वें वित्त आयोग में मोदी सरकार ने 13वें वित्त आयोग में कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार के 30,343 करोड़ रुपये की तुलना में 49,147 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है, जो कांग्रेस की तुलना में डेढ़ गुने से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत अभियान के लिए पांच करोड़, सॉलिड वेस्ट मेनेजमेंट के लिए 70 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 28 करोड़, अमृत मिशन के लिए 593 करोड़, स्वायल हेल्थ कार्ड के लिए तीन करोड़, परम्परागत कृषि सिंचाई योजना के लिए 44 करोड़, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 20 करोड़, ई-नाम योजना में 20 करोड़, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 196 करोड़ और ऑल वेदर रोड के लिए 12,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि चार धाम की यात्रा के लिए 900 किलोमीटर लंबा ऑल वेदर रोड उत्तराखंड में टूरिज्म को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, मुद्रा बैंक योजना के लिए 4,427 करोड़ और उदय डिस्कॉम योजना में लगभग 900 करोड़ रुपया दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 21 लाख जन-धन खाते खोले गए हैं, 24 लाख से अधिक एलईडी बल्ब का वितरण किया गया है और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में राज्य के 1.25 लाख परिवारों को गैस सिलिंडर उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि 'वन रैंक, वन पेंशन' योजना से सबसे ज्यादा फायदा उत्तराखंड को हुआ है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड की त्रिवेन्द्र सिंह रावत सरकार भी उत्तराखंड के विकास के लिए कटिबद्ध है। ■

'ममता सरकार की तुष्टीकरण नीति से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है'

स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, श्री अरबिंदो, रवीन्द्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जैसे मनीषियों ने न केवल देश बल्कि दुनिया भर में बंगाली अस्मिता को प्रतिष्ठित करने का काम किया, लेकिन आज पहले कम्युनिस्ट और बाद में तृणमूल कांग्रेस के शासन के बाद यह महान प्रदेश आज अपने खोये हुए गौरव को फिर से प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 12 सितंबर को कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में जामिनी गैलरी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की तीन वर्ष की उपलब्धियों के साथ-साथ पश्चिम बंगाल की कई ज्वलंत समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा की। अपने उद्बोधन के बाद उन्होंने बुद्धिजीवियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी दिए। इससे पहले उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक हिंसा से पीड़ितों एवं उनके परिजनों से मुलाक़ात की।

राजनीतिक हिंसा के शिकार लोगों से मुलाक़ात के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि शायद ही दुनिया के किसी और हिस्से में इससे ज्यादा राजनीतिक हिंसा होती होगी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विचारधारा से असहमत होने के कारण जिस प्रकार की हिंसा सत्ताधारी पार्टी के लोगों द्वारा की जा रही है, यह दुखद है। क्या गुरु रवींद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद ने इस तरह के बंगाल की कल्पना की थी? तृणमूल कांग्रेस किस प्रकार की संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहती है? उन्होंने कहा कि इस प्रकार की राजनीतिक हिंसा से भारत का विकास नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जो लोग राजनीतिक हिंसा में संलिप्त हैं, ये उनके भले के लिए है कि वे हिंसा छोड़ दें। उन्होंने कहा कि तृणमूल और उसके कैडर जिस प्रकार से विरोधियों को राजनीतिक हिंसा का शिकार बना रहे हैं, उन्हें यह याद होना चाहिए कि वे भी कभी इसी हिंसा के खिलाफ कम्युनिस्टों से लड़े थे और इसलिए राज्य की जनता ने उन्हें इतना बड़ा जनादेश भी दिया। उन्होंने कहा कि यदि कोई सोचता है कि इस प्रकार की हिंसा से भाजपा का विस्तार रुक जाएगा तो वह मुगालते में है। आप भाजपा का जितना दमन करेंगे, जितना अत्याचार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी उतना और आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि मैं दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स चैम्पियन से भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे कोलकाता, बसीरहाट, वीरभूम जैसे जगहों पर हो रही राजनीतिक हिंसा की रिपोर्टिंग करें, क्या यह मानवाधिकार का हनन नहीं है? उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कैडर इस हिंसा और अत्याचार का मजबूती के साथ मुकाबला

करेंगे, हम अपना काम जारी रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।

श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, श्री अरबिंदो, रवीन्द्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जैसे मनीषियों ने न केवल देश बल्कि दुनिया भर में बंगाली अस्मिता को प्रतिष्ठित करने का काम किया, लेकिन आज पहले कम्युनिस्ट और बाद में तृणमूल कांग्रेस के शासन के बाद यह महान प्रदेश आज अपने खोये हुए गौरव को फिर से प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने देश की आजादी के लिए 'दिल्ली चलो' का नारा दिया था। उन्होंने कहा कि जहां से क्रांति की शुरुआत की, जहां से साहित्य की शुरुआत हुई, जहां से रवींद्र संगीत ने पूरे विश्व में पश्चिम बंगाल की संस्कृति का डंका बजाया। वहीं पश्चिम बंगाल आज विकास के दौर में काफी पीछे चला गया है, आज इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का समय आ गया है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पश्चिम बंगाल के विकास के लिए पिछले तीन साल में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कई कार्य किये हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए यूपीए के 13वें वित्त आयोग की तुलना में 14वें वित्त आयोग में लगभग तीन गुना

अधिक राशि दी है। उन्होंने कहा कि 13वें वित्त आयोग में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने पश्चिम बंगाल को शेयर इन सेन्ट्रल टैक्स के तहत 1,03,539 करोड़ रुपये की राशि दी थी, जबकि 14वें वित्त आयोग में मोदी सरकार ने राज्य के लिए 2,89,942 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। उन्होंने कहा कि ग्रांट इन ऐड के रूप में लगभग चार गुना वृद्धि करते हुए पश्चिम बंगाल को 2015-20 के लिए 34,732 करोड़ रुपये जारी किये गए हैं, जबकि यूपीए के 13वें वित्त आयोग में इस क्षेत्र में केवल 9,520 करोड़ रुपये जारी किये गए थे। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में जहां कांग्रेस की यूपीए सरकार ने पश्चिम बंगाल को कोई मदद नहीं दी थी, वहीं मोदी सरकार ने तमाम वैचारिक मतभेदों के बावजूद पश्चिम बंगाल को 11,760 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि लोकल बॉडीज ग्रांट के रूप में पश्चिम बंगाल को कांग्रेस की यूपीए सरकार ने महज 1,444 करोड़ रुपये ही दिए थे, जबकि मोदी सरकार ने इसमें लगभग साढ़े चौदह गुने की भारी बढ़ोतरी करते हुए पश्चिम बंगाल के लिए 20,832 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड और नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में भी काफी वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि इन सभी को जोड़ दिया जाय तो 13वें वित्त आयोग में कांग्रेस की सोनिया-मनमोहन सरकार ने पश्चिम बंगाल को जहां 1,32,783 करोड़ रुपये की राशि दी थी, वहीं मोदी सरकार ने 3,59,406 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। उन्होंने कहा कि हम तो पश्चिम बंगाल के विकास के लिए ग्रांट भेज रहे हैं, लेकिन क्या ये राशि राज्य के विकास के लिए खर्च हो रही है? उन्होंने कहा कि इन ग्रांट्स के अतिरिक्त केन्द्रीय योजनाओं में तीन साल में पश्चिम बंगाल को 24,705 करोड़ रुपये दिए गए हैं। मुद्रा बैंक योजना में लगभग 29 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं और खदानों की ई-नीलामी से अर्जित राशि में से पश्चिम बंगाल को 21345 करोड़ रुपये दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं मीडिया के माध्यम से ममता दीदी को पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के विकास के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसका हिसाब तो दे दिया लेकिन पैसा कहां गया, इसकी जवाबदेही किसकी है? उन्होंने कहा कि इसका हिसाब ममता बनर्जी को देना है। उन्होंने कहा कि क्यों इतने सालों बाद भी पश्चिम बंगाल के गांवों में बिजली नहीं आई, राज्य की साक्षरता दर क्यों नहीं बढ़ी, औद्योगिक विकास नहीं हुआ, स्वच्छ पीने का पानी नहीं पहुंचा, आखिर कहां गया पैसा, ये सारा पैसा सिंडिकेटों में समाप्त हो जाता है।

उन्होंने कहा कि आज पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिले विभाजन से पहले की स्थिति में फिर से आ गए हैं। ममता सरकार की तुष्टिकरण नीति से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है, राज्य में बम धमाके हो रहे हैं, जाली नोटों का कारोबार फ़ैल रहा है, गायों की तस्करी हो रही है। आखिर क्या हो रहा है आज पश्चिम बंगाल में? उन्होंने कहा कि मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है, मां सरस्वती की पूजा नहीं करने देते - ये किस प्रकार के पश्चिम बंगाल का निर्माण हम कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम किसी के विरोधी नहीं हैं और बंगाल के लोग तो किसी के विरोधी हो ही नहीं सकते, लेकिन हमारी परंपराओं का ही कोई विरोध करे, इस प्रकार की सोसायटी तो नहीं चल सकती है न? उन्होंने कहा कि देश में कई धर्मों के जुलूस एक साथ निकलते हैं, पश्चिम बंगाल में भी निकलते रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि पश्चिम बंगाल में ऐसे फैसले हो रहे हैं - ये फैसले हिन्दू-मुसलमान के कारण नहीं बल्कि वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति के कारण लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगालवासियों को अपना सहज स्वभाव छोड़ कर निर्णायक बनने का समय आ गया है। राज्य के गरीब लोगों का और राज्य के भविष्य के लिए जब तक आप पहल नहीं करेंगे, तब तक पश्चिम बंगाल आगे नहीं बढ़ सकता। ■

'सौभाग्य' योजना का शुभारंभ

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना 'सौभाग्य' नामक नई योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 25 सितंबर को किया गया। इसका उद्देश्य अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चत करते हुए सभी घरों में बिजली पहुंचाना और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी शेष गैर विद्युतिकृत घरों में बिजली कनेक्शन सुलभ कराना है, ताकि देश में सभी घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

इस परियोजना की कुल लागत 16,320 करोड़ रुपए है और इसमें 12,320 करोड़ रुपए का सकल बजट सहयोग (जीबीएस) प्रदान दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना की कुल लागत 14,025 करोड़ रुपए है और इसके लिए 10,587.50 करोड़ रुपए का सकल बजट सहयोग प्रदान किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों के लिए योजना की कुल लागत 2,295 करोड़ रुपए है और इसके लिए 1,732.50 करोड़ रुपए का सकल बजट सहयोग प्रदान किया जाएगा। केंद्र सरकार इस योजना के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को बड़े स्तर पर वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

इस योजना के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 दिसंबर, 2018 तक सभी घरों में बिजली पंहुचाने का कार्य पूर्ण करना होगा। योजना के अंतर्गत निःशुल्क बिजली कनेक्शन के लिए लाभकर्ता का चयन वर्ष 2011 की सामाजिक आर्थिक और जाति जनसंख्या (एसईसीसी) द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही एसईसीसी आंकड़ें के तहत बिना बिजली वाले घरों में भी मात्र 500 रूपए के भुगतान द्वारा कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। यह राशि बिजली बिल की 10 किस्तो में वापिस की जाएगी। ■

'गुजरात की समृद्धि में सहकारी संस्थाओं का योगदान अमूल्य है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 18 सितंबर को गुजरात यूनिवर्सिटी कन्वेंशन सेंटर, अहमदाबाद (गुजरात) में आयोजित सहकार सम्मेलन को संबोधित किया और उनसे भारतीय जनता पार्टी के मिशन गुजरात की उन्नति के लिए कार्य करने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि लंबे समय से गुजरात में सहकारी संस्थाएं राज्य के सशक्त विकास के लिए अनवरत कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सच्चे अर्थों में महात्मा गांधी के सहकारिता के सिद्धांत को नीचे तक ले जाने में गुजरात की सहकारी संस्थाओं ने उत्कृष्ट काम किया है। उन्होंने कहा कि गुजरात की समृद्धि में यहां की सहकारी संस्थाओं का योगदान अमूल्य है। उन्होंने कहा गुजरात में सहकारी संस्था के बतौर अमूल ने दूध और दुग्ध उत्पादों के उत्पादन में एक मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि अमूल का मॉडल पूरे विश्व को अचंभित करने वाला है। उन्होंने कहा कि सौ वर्षों से भी अधिक समय से सहकारी संस्थाएं उसी मजबूती के साथ गुजरात के विकास में अपना योगदान दे रही हैं, ये भी एक शोध का विषय है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हमें समय-समय पर सहकारी क्षेत्रों में सुधार पर भी पुनर्विचार करना चाहिए, ताकि इन क्षेत्रों की समस्याओं का उचित समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि जब माधुपुरा सहकारी बैंक जैसी घटनाओं से सहकारी बैंकिंग व्यवस्था टूटने की कगार पर पहुंच गई थी, तब राज्य की नरेन्द्र मोदी सरकार ने राजनैतिक इच्छाशक्ति से हिम्मत के साथ सहकारी क्षेत्र के लिए सुधार की पहल की और गुजरात का सहकारी क्षेत्र फिर से उठ खड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए श्री नरेन्द्र भाई मोदी ने राज्य के सहकारी क्षेत्रों के सुधार के लिए जो मुहिम चलाई, यह उसी का परिणाम है कि आज गुजरात का सहकारी क्षेत्र मजबूत एवं सुदृढ़ है।

उन्होंने कहा कि जहां पहले सहकारी क्षेत्रों में जमाकर्ता को इंश्योरेंस नहीं मिलता था, वहीं 2010 तक उन्हें 1100 करोड़ रुपये देने में सहकारी संस्थाएं कामयाब रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की श्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने सहकारी क्षेत्रों में सुधार का परिवर्तन करने में मदद की। उन्होंने कहा कि डेयरी उद्योग के विकास के लिए भी मुख्यमंत्री के रूप में श्री नरेन्द्र मोदी ने कई कदम उठाये। उन्होंने कहा कि पहले केवल दक्षिणी और उत्तरी गुजरात में ही डेयरी उद्योग विकसित था, मोदी जी ने इसे सौराष्ट्र से लेकर कच्छ तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि गांधी जी के खुली सदस्यता के सिद्धांत के आधार पर चल रहे डेयरी उद्योग आज राज्य के 10 जिलों के किसानों

की आजीविका का मुख्य साधन है। श्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से गुजरात के हर जिले में डेयरी की सहकारी संस्थाएं बनीं। उन्होंने कहा कि पहले राज्य की सहकारी संस्थाएं किसानों को 14% ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध कराती थी, आज केवल 1% पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सस्ते दरों पर ऋण उपलब्ध कराकर किसानों को ताकत देने का काम गुजरात की नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया। उन्होंने कहा कि गुजरात की भाजपा सरकार ने राज्य के लगभग 65 हजार से अधिक सहकारी मंडियों को कम्प्यूटर दिया, मोदी सरकार ने नाबार्ड को खेती के लिए दी जाने वाली 21 हजार करोड़ रुपये की राशि को बढ़ा कर 41 हजार करोड़ रुपये कर दिया, यह अपने आप में एक बड़ा कदम है।

उन्होंने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में भी गुजरात के विकास के लिए कई कार्य किये हैं। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की यूपीए सरकार थी, तब गुजरात को विकास के लिए केवल 63,346 करोड़ रुपए मिलते थे, आज जब केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब गुजरात को 1,58,377 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू हो, हाइवे हो या नर्मदा योजना, हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के लिए काफी काम किया है। ■

पत्र-पत्रिकाओं से...

सुधारात्मक पहलें

रघुवर दास के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार ने एक हजार दिन पूरे कर लिए हैं। पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ गठित इस सरकार ने निश्चित रूप से कई ऐसे काम किए जो राज्य के विकास में मील के पत्थर साबित होंगे। कई महत्वपूर्ण नीतियां लागू हुईं। इनमें से कुछ तो लंबे समय से लटकी हुई थीं। स्थानीय नीति लागू करना इनमें से एक है। इससे राज्य में नियुक्तियों के दरवाजे खुल गए। न केवल सरकारी विभागों व कार्यालयों के रिक्त पद भरे जाने लगे, बल्कि युवाओं को नौकरियां मिलनी शुरू हुईं। इस सरकार ने कई सुधारात्मक पहल भी किए। विकास दर के मामले में झारखंड देश में दूसरे नंबर पर पहुंचा, तो नक्सलियों पर भी अंकुश लगा।

— दैनिक जागरण (२३ सितंबर)

ममता सरकार को झटका

कलकत्ता हाईकोर्ट ने विजयादशमी पर प्रतिमा विसर्जन से जुड़े मामले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के फैसले को पूरी तरह पलटते हुए उसे बड़ा झटका दिया है। इस बार 30 सितंबर को विजयादशमी और 1 अक्टूबर को मोहर्रम पड़ रहा है। कानून-व्यवस्था पर संभावित खतरे की बात कहते हुए सरकार ने 30 सितंबर यानी दशमी को रात 10 बजे के बाद और एक अक्टूबर को पूरी तरह प्रतिमा विसर्जन पर रोक लगा दी थी। सरकार के इसी फैसले के खिलाफ दायर तीन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मोहर्रम समेत हर दिन दोपहर 12 बजे तक प्रतिमा विसर्जन की इजाजत तो दी ही, साथ में सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि सरकार के पास अधिकार है, इसका मतलब यह नहीं कि वह अधिकारों का बेजा इस्तेमाल कर सकती है। बिना किसी ठोस वजह के नागरिकों के अधिकार नहीं छीने जा सकते।

—नवभारत टाइम्स (२३ सितंबर)

स्वस्थ भारत – सबल भारत

अमृत स्टोर–कैंसर और हृदयवाहिनी बीमारियों की किफायती दवाइयां और इम्पलांट्स को बाजार मूल्य से 60 से 90 प्रतिशत कम कीमत पर उपलब्ध कराते हैं। अब तक 83 स्टोर खोले गए। इसके परिणामस्वरूप अब तक लाभान्वित रोगियों की कुल संख्या 17.97 लाख। 58 करोड़ रुपये से अधिक लागत की दवाओं और इम्पलांट को 23 करोड़ रुपये से कम राशि में बेचा गया। अब तक रोगियों को प्रदत्त कुल अधिकतम रिटेल मूल्य : 75.23 करोड़ रुपए। अब तक रोगियों को हुई कुल बचत : 103.55 करोड़ रुपए।

— पीआइबी

सफल 'मन की बात'

मन की बात कार्यक्रम को उल्लेखनीय सफलता मिली है। लाखों लोग प्रधानमंत्री की बात सुनते हैं और उन तक अपनी बात पहुंचाते हैं। पिछले तीन वर्षों में जिस तरह प्रधानमंत्री को आम लोगों ने करीब डेढ़ लाख चिट्ठियां भेजीं और छह लाख लोगों ने फोन किए। उससे यदि कुछ स्पष्ट होता है तो यही कि आम जनता संवाद की इस शैली की महत्ता को समझ चुकी है। आज यदि साफ-सफाई को लेकर लोगों में जागरूकता और सतर्कता बढ़ी है तो इसके पीछे मन की बात कार्यक्रम ही है। इसी तरह इस कार्यक्रम ने अन्य सामाजिक समस्याओं के मामले में भी जनता को सचेत करने का काम किया है।

— दैनिक जागरण (२५ सितंबर)

स्फुट विचार...

धर्म और व्यावहारिक जीवन अलग नहीं हैं। संन्यास लेना जीवन का परित्याग करना नहीं है। असली भावना सिर्फ अपने लिए काम करने की बजाए देश को अपना परिवार बनाकर मिल-जुलकर काम करना है। इसके बाद का कदम मानवता की सेवा करना है और अगला कदम ईश्वर की सेवा करना है।

- लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक

निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रुढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है वो खुद को गलत स्थिति में पंहुचा देता है।

- महात्मा गांधी

बीज की एक इकाई विभिन्न रूपों में प्रकट होती है – जड़ें, तना, शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल। इन सबके रंग और गुण अलग-अलग होते हैं। फिर भी बीज के द्वारा हम इन सबके एकत्व के रिश्ते को पहचान लेते हैं।

- पं. दीनदयाल उपाध्याय

व्यक्तिगत और पारिवारिक स्वार्थ-साधना को एक ओर रखकर हमें राष्ट्र की आकांक्षा प्रदीप्त करनी होगी। दलगत स्वार्थों की सीमा छोड़कर विशाल राष्ट्र की हित-चिंता में अपना जीवन लगाना होगा। हमारी विजिगीषु वृत्ति हमारे अन्दर अनंत गतिमय कर्मचेतना उत्पन्न करे।

- अटल बिहारी वाजपेयी

प्रस्तुति: पंकज आनंद

हमारे सम्मानित आजीवन सदस्यगण

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री, भारत
श्री अमित शाह
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री अरुण जेटली
केंद्रीय वित्त एवं रक्षा मंत्री
श्री राधा मोहन सिंह
केंद्रीय कृषि मंत्री
श्री प्रकाश जावडेकर
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री
श्री जगत प्रकाश नड्डा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री
श्रीमती मेनका संजय गांधी
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री
श्री अर्जुन राम मेघवाल
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट राज्यमंत्री
श्री विष्णुदेव साय
केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री
श्री बाबुल सुप्रियो
केंद्रीय भारी उद्योग राज्यमंत्री
श्री मनोहर पर्रिकर
मुख्यमंत्री, गोवा

श्री भूपेन्द्र यादव, सांसद
भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री
श्री अरुण सिंह
भाजपा राष्ट्रीय महासचिव
श्री शांता कुमार, सांसद
पूर्व मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश
श्री गोपाल नारायण सिंह
सांसद (राज्यसभा)
डॉ. गोकाराजू गंगा राजू
सांसद (लोकसभा)
श्री महेश पोद्दार
सांसद (राज्यसभा)
श्री अनिल शिरोले
सांसद (लोकसभा)
श्री मनोज राजोरिया
सांसद (लोकसभा)
श्री रवींद्र कुमार राय
सांसद (लोकसभा)
श्री दिलीप कुमार गांधी
सांसद (लोकसभा)
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल
राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

पं. दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी पर नई दिल्ली में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

पं. दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी पर नई दिल्ली में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

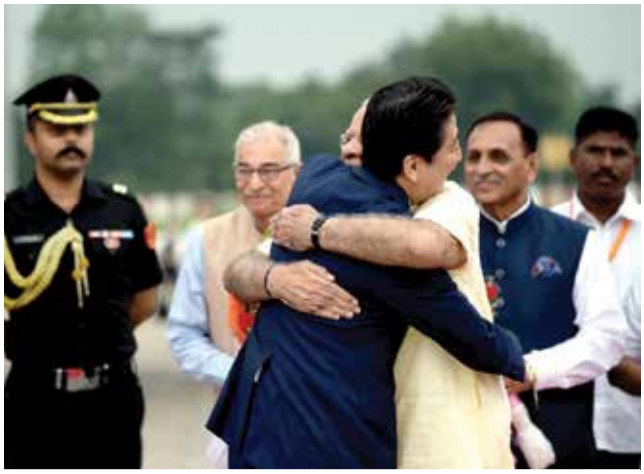

अहमदाबाद हवाई अड्डे पर जापान के प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे

जापान के प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे के सम्मान में अहमदाबाद में आयोजित सांस्कृतिक रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

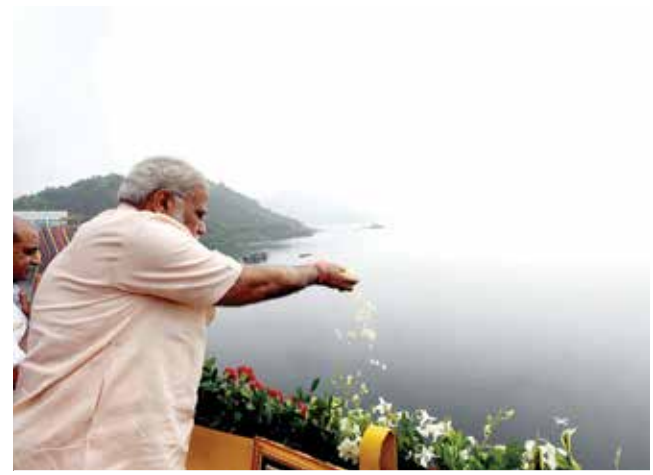

गुजरात में सरदार सरोवर बांध पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2015-17
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2015-17